● वर्ष-6
● अंक-25
रायपुर, शुक्रवार
04 सितंबर 2026
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8>> समरसता के संकल्प के साथ ...

भारत-बेल्जियम संबंध: मोदी से मिले प्रधानमंत्री वेवर

जोरावर टैंक, क्लीन एनर्जी समेत कई मुद्दों पर मंथन

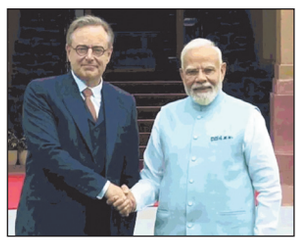

नई दिल्ली। भारत, यूरोपीय संघ और यूरोप के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर से मुलाकात की। दोनों नेताओं की यह मुलाकात राजधानी स्थित हैदराबाद हाउस में हुई।

इससे पहले, प्रधानमंत्री डी वेवर ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने वहां पुष्पांजलि अर्पित की और फूल चढ़ाए। बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने राजघाट पर विजिटर्स बुक में भी हस्ताक्षर किए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि भारत और बेल्जियम के संबंध सहयोग के पारंपरिक क्षेत्रों से आगे बढ़कर रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक फैल गए हैं। उन्होंने जोरावर टैंक और आंध्र प्रदेश में एक बड़े ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट पर सहयोग का जिक्र किया। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर के साथ संयुक्त बयान देते हुए यह बात कही।

पीएम मोदी ने कहा, आज हमारे सहयोग का दायरा पारंपरिक क्षेत्रों से आगे बढ़कर रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक फैल गया है। हम जोरावर टैंक जैसे आधुनिक रक्षा उपकरणों पर मिलकर काम कर रहे हैं। हम आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट्स में से एक को भी विकसित कर रहे हैं।

उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों के ऐतिहासिक महत्व पर भी जोर दिया और कहा, भारत और बेल्जियम के संबंध इतिहास में गहराई से जुड़े हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बेल्जियम में हजारों भारतीय सैनिकों का साहस और बलिदान हमारी साझा यादों का एक अहम हिस्सा है। आज, लोकतांत्रिक मूल्य, बाजार-आधारित अर्थव्यवस्था और लोगों के बीच मजबूत संबंध हमें स्वाभाविक साझेदार बनाते हैं। भारत और ईयू के बीच हुए एफटीए की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने निवेश के लिए एक फास्ट-ट्रैक मैकेनिज्म बनाया है। उन्होंने कहा, इस साल की शुरुआत में, हमने भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को अंतिम रूप दिया।

यह दुनिया की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकतों के बीच यह अभूतपूर्व सहयोग वैश्विक स्थिरता, विकास और साझा समृद्धि को और मजबूत करेगा। भारत की लगातार आर्थिक प्रगति और इस समझौते ने हमारे आर्थिक संबंधों के लिए नई संभावनाएं खोली हैं। आज, हमने इन संभावनाओं को ठोस नतीजों में बदलने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

हमने भारत-बेल्जियम बिजनेस फोरम को एक नियमित व्यवस्था बनाने का फैसला किया है। हम दोनों देशों के वित्तीय, फिनटेक और नियामक संस्थानों के बीच तालमेल बढ़ाएंगे और इन उपायों के जरिए अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य हासिल करेंगे।

उन्होंने कहा, आज हमने अपने स्टार्टअप्स के बीच संबंध मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र में क्षमता निर्माण को बढ़ाने पर सहमति जताई। हम यूनिवर्सिटी और रिसर्च के क्षेत्रों में भी सहयोग को मजबूत करेंगे। जल्द ही प्रतिभाओं की आवाजाही को आसान बनाने के लिए माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करेंगे। आज हमने क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विस्तार से चर्चा की। भारत और बेल्जियम दोनों ही कानून के शासन, बातचीत और कूटनीति में विश्वास रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर डी वेवर 4 सितंबर तक भारत के दौरे पर हैं। इस दौरे का मकसद दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को और मजबूत करना तथा व्यापार, निवेश, रक्षा, तकनीक और कनेक्टिविटी के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना है। फरवरी 2025 में पद संभालने वाले डी वेवर बेल्जियम के प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार भारत का दौरा कर रहे हैं। यह दौरा दो दशकों में किसी बेल्जियम के प्रधानमंत्री की भारत की पहली यात्रा भी है। उनके साथ बेल्जियम के रक्षा और विदेश व्यापार मंत्री थियो फ्रैंकन और अधिकारियों व बिजनेस लीडर्स का एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। जिसमें बेल्जियम के रक्षा उद्योग के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह दौरा भारत और बेल्जियम के संबंधों में आई तेजी के बीच हो रहा है।

हिमालय पर बढ़ते खतरे की तैयारी शुरू

गृह विभाग की उच्चस्तरीय बैठक हुई

नई दिल्ली । नई दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में हुई हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की उच्चस्तरीय बैठक ऐसे समय में हुई है, जब नेपाल में हाल में आई भीषण हिमालयी आपदा ने पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चेतावनी पैदा कर दी है। हम आपको बता दें कि नेपाल-तिब्बत सीमा क्षेत्र में अगस्त के अंत में ग्लेशियर और चट्टानी हिस्से के विशाल ढहाव के बाद आई विनाशकारी बाढ़ ने हजारों लोगों को प्रभावित किया है। ताजा रिपोर्टों के अनुसार मृतकों की संख्या एक हजार से अधिक हो चुकी है और हजारों लोग अब भी लापता हैं।

इस पृष्ठभूमि में भारत द्वारा ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड और हिमस्खलन के खतरों पर की गई यह समीक्षा बदलते हिमालयी पर्यावरण के सामने एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय रणनीतिक पहल है। हम आपको बता दें कि बैठक में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिवों तथा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों के साथ गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, केंद्रीय जल आयोग, भारत मौसम विज्ञान विभाग और रक्षा भू-सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। केंद्रीय गृह सचिव ने विशेष रूप से संवेदनशील ग्लेशियल झीलों, हिमस्खलन संभावित क्षेत्रों और संभावित जल-प्रवाह मार्गों की निरंतर एवं सक्रिय निगरानी पर जोर दिया।

देखा जाये तो नेपाल की ताजा त्रासदी ने इस आवश्यकता को और स्पष्ट कर दिया है। वैज्ञानिक अध्ययनों और उपग्रह विश्लेषणों के अनुसार यह घटना सामान्य नदी-बाढ़ नहीं थी। नेपाल के लांगटांग क्षेत्र के निकट ग्लेशियर और चट्टान का एक बड़ा हिस्सा ढहा, जिसके बाद बर्फ, पानी, चट्टानों और मलबे का विशाल प्रवाह संकरी हिमालयी घाटियों से नीचे आया और विनाशकारी फ्लैश फ्लड में बदल गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि बढ़ते तापमान, ग्लेशियरों के पिघलने और पर्माफ्रॉस्ट के कमजोर होने से ऊंचाई वाले पर्वतीय ढलान अधिक अस्थिर हो रहे हैं। हालांकि किसी एक घटना को सीधे जलवायु परिवर्तन से जोड़ने के लिए विस्तृत वैज्ञानिक जांच आवश्यक होती है, लेकिन गर्म होते हिमालय में ऐसी घटनाओं की संभावना बढ़ने पर व्यापक वैज्ञानिक सहमति है।

राजनाथ ने रक्षा कूटनीति पर रक्षा दस्तावेज जारी किया

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को यहां रक्षा कूटनीति पर रक्षा दस्तावेज का विमोचन किया जिसमें अगले 10 वर्षों के लिए वैश्विक रक्षा साझेदारियों के संबंध में भारत के रणनीतिक रोडमैप और दृष्टिकोण की रूपरेखा दी गई है।रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दस्तावेज में राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों को सक्रिय वैश्विक सहयोग के साथ जोड़ने पर जोर दिया गया है, जिससे दीर्घकालिक स्थिरता और पारस्परिक विकास को बढ़ावा मिल सके। रक्षा दस्तावेज में रणनीतिक साझेदारी, क्षमता विकास, स्वदेशी रक्षा निर्यात और समुद्री सुरक्षा को प्रमुख स्तंभ बनाया गया है।इसके तहत द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सुरक्षा सहयोग मजबूत करने, संयुक्त सैन्य अभ्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने तथा मित्र देशों के साथ रक्षा के सर्वोत्तम तौर-तरीकों को साझा करने पर जोर दिया गया है। साथ ही भारत में निर्मित रक्षा प्लेटफार्मों को बढ़ावा देकर देश को विश्वसनीय वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है। इसमें रक्षा कूटनीति को विदेश नीति का मुख्य स्तंभ बताते हुए बदलते वैश्विक परिदृश्य में शांति, स्थिरता और नियम-आधारित व्यवस्था में भारत की भूमिका मजबूत करने का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है।इस अवसर पर सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, रक्षा उत्पादन सचिव संजीव कुमार, विदेश मंत्रालय में सचिव रुद्रेंद्र टंडन, वायु सेना उप प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, नौसेना उप प्रमुख वाइस एडमिरल अजय कोचर, एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख एयर मार्शल तेजिंदर सिंह और रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

रायगढ़ की बेटियों ने अंतरराष्ट्रीय खेल मंच पर बढ़ाया देश का मान : वित्त मंत्री

रायपुर। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय लैक्रॉस टूर्नामेंट में भारतीय महिला लैक्रॉस टीम द्वारा कांस्य पदक जीतने पर हर्ष व्यक्त किया है। उन्होंने रायगढ़ जिले की तीन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों सोनम बंजारा, शांति प्रधान और मानसी भूमिया को इस शानदार उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं दी हैं। वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि रायगढ़ की बेटियों ने अंतरराष्ट्रीय खेल मंच पर शानदार प्रदर्शन कर देश और छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है। भारतीय महिला लैक्रॉस टीम ने टूर्नामेंट में बेहतरीन खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए सिंगापुर को पराजित कर कांस्य पदक अपने नाम किया।

टीम की इस सफलता में रायगढ़ की तीनों खिलाड़ियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि रायगढ़ सहित पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है। सोनम बंजारा, शांति प्रधान और मानसी भूमिया की सफलता प्रदेश की अन्य बेटियों और युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बनेगी।

जन्माष्टमी पर इसरो करेगा ईओएस-5 का प्रक्षेपण

नई दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) एक बार फिर अंतरिक्ष में अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार है। शुक्रवार, 4 सितंबर की तड़के 2:55 बजे श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ईओएस-5 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाएगा। इसे भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान-एफ17 के जरिए अंतरिक्ष में स्थापित किया जाएगा।

यह उपग्रह भारत की अंतरिक्ष आधारित निगरानी क्षमता को मजबूत करेगा। इससे देश की सीमाओं, समुद्री क्षेत्रों, मौसम संबंधी गतिविधियों और आपदा संभावित इलाकों पर लगातार नजर रखने में मदद मिलेगी।

ईओएस-5 भारत की निगरानी क्षमता को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण उपग्रह है। यह पृथ्वी की सतह से करीब 36 हजार किलोमीटर की ऊंचाई से भारत के बड़े हिस्से पर लगातार नजर रखने में सक्षम होगा। इसमें लगे उच्च क्षमता वाले कैमरों से पृथ्वी की सतह की विस्तृत तस्वीरें प्राप्त की जा सकेंगी।उपग्रह को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे प्रक्षेपण स्थल से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसे उप-भूस्थिर स्थानांतरण कक्षा में स्थापित किया जाएगा। ईओएस-5 की सबसे बड़ी विशेषताओं में इसकी निगरानी क्षमता शामिल है। इसके जरिए देश की सीमाओं, समुद्री क्षेत्रों और संवेदनशील इलाकों पर लगातार नजर रखी जा सकेगी। उच्च क्षमता वाली तस्वीरें सुरक्षा एजेंसियों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं।

प्रमुख समाचार

वाराणसी में बाढ़: पीएम मोदी ने डीएम से फोन पर ली जानकारी

वाराणसी। काशी के सांसद एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से टेलीफोन पर वार्ता कर वाराणसी में बाढ़ की स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने गंगा के बढ़ते जलस्तर, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और राहत शिविरों में की जा रही व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने प्रभावित लोगों को किसी तरह की परेशानी न होने देने और राहत कार्य युद्धस्तर पर चलाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने जिलाधिकारी से राहत शिविरों में उपलब्ध कराई जा रही भोजन, पेयजल समेत अन्य आवश्यक सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों की राहत के लिए प्रशासन पूरी तत्परता से कार्य करे और उन्हें तत्काल आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन क्षेत्रों में राहत सामग्री की अतिरिक्त आवश्यकता हो, वहां तत्काल उसकी व्यवस्था की जाए। प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री और अन्य जरूरी सहायता तेजी से पहुंचाई जाए।

पंजाब की वोटर लिस्ट से नाम हटने पर भड़के राघव चड्ढा

चंडीगढ़। पंजाब में वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट को लेकर सियासत गरमा गई है। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने गुरुवार को दावा किया कि पंजाब की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम कथित तौर पर शिफ्टेड (दूसरी जगह स्थानांतरित) की श्रेणी में डाल दिया गया है। चड्ढा ने इसके पीछे सत्ताधारी आम आदमी पार्टी पर राजनीतिक बदले की भावना से काम करने का गंभीर आरोप लगाया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (ट्विटर) पर एक विस्तृत पोस्ट साझा करते हुए राघव चड्ढा ने कहा कि यह कोई प्रशासनिक या क्लर्क की गलती नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद से आप नेतृत्व उनसे बदला लेने की कोशिश कर रहा है। एक्स पर एक लंबी पोस्ट में, चड्ढा ने दावा किया कि यह कोई क्लर्क की गलती नहीं है, बल्कि राजनीतिक बदले का मामला है। एसआईआर के हर स्तर पर - बीएलओ से लेकर पंजाब के चीफ़ इलेक्टोरल ऑफ़िसर तक - पंजाब सरकार के कर्मचारी तैनात हैं।

बसपा 2027 उत्तरप्रदेश चुनाव अकेले लड़ेगी : मायावती

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने गुरुवार को घोषणा की कि पार्टी पूरे भारत में आने वाले सभी चुनाव अकेले लड़ेगी, जिसमें 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भी शामिल हैं। बीएसपी की अखिल भारतीय बैठक में बोलते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी किसी भी चुनाव के लिए गठबंधन पर निर्भर नहीं रहेगी, चाहे चुनाव बड़ा हो या छोटा। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद की भूमिका पर भी बात की। उन्होंने कहा कि हालांकि उन्हें पार्टी में सक्रिय रहने की इजाज़त है, लेकिन उन्हें और अधिक परिपक्वता लाने की ज़रूरत है और फिलहाल उन्हें कोई बड़ी ज़िम्मेदारी नहीं सौंपी जाएगी। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि पार्टी का मुख्य ध्यान बहुजन समाज के हितों और शोषित समुदायों को शासक वर्ग बनाने के मिशन पर है, और इस लक्ष्य को पाने के लिए राजनीतिक सत्ता हासिल करना जरूरी है। यह घोषणा बसपा के 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में अकेले चुनाव लड़ने के बाद आई है।

मद्रास हाईकोर्ट ने स्टालिन की याचिका खारिज की

चेन्नई। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के प्रेसिडेंट एमके स्टालिन को गुरुवार को मद्रास हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा, जिसने कोलाथुर असेंबली सीट पर उनकी चुनावी हार को लेकर उनकी अर्जी खारिज कर दी। यह ऑर्डर दो जजों की बेंच ने पास किया, जिसमें कहा गया कि तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री की अर्जी मेंटेनेबल नहीं है। कोलाथुर स्टालिन का गढ़ रहा था, लेकिन वह हाल ही में हुए तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन में तमिलगा वेत्री कड़गम (टीवीके) लीडर वीएस बाबू से करीब 8,000 वोटों के मार्जिन से हार गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया के मुताबिक, स्टालिन को 74,202 (40.32 परसेंट) वोट मिले, जबकि बाबू को 82,997 (45.09 परसेंट) वोट मिले। 4 मई को नतीजे घोषित होने के बाद, डीएमके प्रमुख ने 7 मई को वेरिफिकेशन के लिए अर्ज़ी दी, जिसकी प्रक्रिया 29 जुलाई को शुरू हुई। उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट का भी रुख किया और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में खराबी का हवाला देते हुए नतीजों में गड़बड़ी का आरोप लगाया।

अभिषेक के ऑफिस में तोड़फोड़ टीएमसी-भाजपा में जुबानी जंग तेज

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता अभिषेक बनर्जी के कोलकाता के कैमक स्ट्रीट स्थित ऑफिस में कथित तौर पर तोड़-फोड़ और हिंसा के बाद राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। टीएमसी नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी समर्थित गुंडों ने ऑफिस में घुसकर सुरक्षाकर्मियों के साथ मारपीट की। इन आरोपों को खारिज करते हुए पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रमुख ने कहा कि पार्टी का इस घटना से कोई लेना-देना नहीं है और उन्होंने इस तोड़-फोड़ को टीएमसी की अंदरूनी कलह का नतीजा बताया। बीजेपी ने कहा कि वह लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करती है, जबकि टीएमसी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ रहे हैं। इस बीच, कोलकाता पुलिस और नगर निगम के अधिकारी पहले ही एक अवैध बिलबोर्ड विवाद के सिलसिले में उस जगह का दौरा कर चुके हैं और ऑफिस में हुई तोड़-फोड़ की जांच चल रही है। बताया जा रहा है कि तोड़-फोड़ की यह घटना गुरुवार सुबह करीब 4:30 बजे हुई। बाद में, कोलकाता पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में छह लोगों को गिरफ़्तार किया।

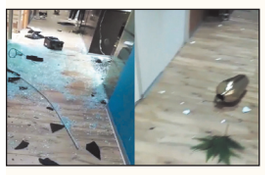

नितिन की बैठक से भाजपा ने खोला 2027 का चुनावी मोर्चा

कांतिलाल मांडोत

भारतीय जनता पार्टी ने 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच युवाओं को अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर गंभीरता से काम शुरू कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं के साथ हुई अहम बैठक को इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बैठक में युवाओं तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने, नई पीढ़ी के बीच संगठन की स्वीकार्यता मजबूत करने और आगामी विधानसभा चुनावों में युवा मतदाताओं की भूमिका को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात सहित सात राज्यों में होने वाले चुनावों को देखते हुए भाजपा अब युवाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुट गई है।

भाजपा की नई रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पार्टी अब युवाओं से केवल राजनीतिक मुद्दों के आधार पर संवाद करने के बजाय उनके रोजमर्रा के सवालों, आकांक्षाओं और चिंताओं को भी अपने अभियान का हिस्सा बनाने की तैयारी कर रही है। रोजगार, शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाएं, कौशल विकास, नशे की समस्या, डिजिटल दुनिया और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दे आने वाले समय में पार्टी के संवाद का प्रमुख आधार बन सकते हैं। इसके पीछे स्पष्ट राजनीतिक उद्देश्य भी है। देश की बड़ी युवा आबादी चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाती है और नई पीढ़ी का रुख किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष में माहौल बनाने की क्षमता रखता है।

नितिन नवीन की बैठक में भाजपा युवा मोर्चा के नवनियुक्त अध्यक्ष हेमांग जोशी के साथ पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर, पूनम महाजन और तेजस्वी सूर्या जैसे युवा चेहरों की मौजूदगी भी इस बात का संकेत है कि पार्टी युवाओं से जुड़े अभियान में अपने पुराने और नए दोनों नेतृत्व को सक्रिय करना चाहती है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, युवा मामलों एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया तथा केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित कई वरिष्ठ नेता भी बैठक में शामिल हुए। स्मृति ईरानी, गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी और छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा जैसे नेताओं की भागीदारी से साफ है कि यह केवल युवा मोर्चे की बैठक नहीं थी, बल्कि व्यापक राजनीतिक रणनीति तैयार करने का प्रयास था।सूत्रों के अनुसार, इस महत्वपूर्ण विमर्श के लिए देशभर से 40 से अधिक नेताओं को आमंत्रित किया गया था। पार्टी की ओर से बैठक में हुई चर्चाओं पर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन बैठक का समय और इसमें शामिल नेताओं का स्वरूप बताता है कि भाजपा 2027 के चुनावों को लेकर अभी से जमीन तैयार करना चाहती है। खासतौर पर जेन जी यानी नई पीढ़ी के मतदाताओं को लेकर पार्टी को अपनी रणनीति में बदलाव की आवश्यकता महसूस हो रही है।हाल के वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं, रोजगार, शिक्षा और अवसरों से जुड़े मुद्दों को लेकर युवाओं में असंतोष देखने को मिला है। नीट जैसी परीक्षाओं से जुड़े विवादों ने भी युवा वर्ग में नाराजगी को राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनाया। ऐसे माहौल में भाजपा के सामने चुनौती केवल सरकार की उपलब्धियां गिनाने की नहीं, बल्कि युवाओं की शिकायतों को सुनने और उन्हें यह भरोसा दिलाने की है कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से लिया जा रहा है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित करते हुए फ्रेंड्स शब्द का इस्तेमाल इसी संवाद की शैली का हिस्सा माना जा सकता है। संदेश यह है कि सरकार और पार्टी नई पीढ़ी को अपने विरोधी खेमे के रूप में नहीं देखती। युवाओं की नाराजगी को राजनीतिक टकराव में बदलने के बजाय उनके साथ संवाद स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस रणनीति की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि युवाओं की वास्तविक समस्याओं के समाधान को कितना प्रभावी ढंग से जमीन पर उतारा जाता है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 137वें एपिसोड में युवाओं से नशामुक्त भारत अभियान को जन आंदोलन बनाने की अपील की। उन्होंने युवाओं से नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने वाले वीडियो और अन्य रचनात्मक कंटेंट तैयार करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने माना कि युवाओं की रचनात्मक क्षमता और सोशल मीडिया की व्यापक पहुंच का इस्तेमाल नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने में किया जा सकता है।राजनीतिक दृष्टि से देखें तो नशामुक्ति का मुद्दा भाजपा के लिए युवाओं तक पहुंच बनाने का एक प्रभावी माध्यम बन सकता है।

एआई की नई राजधानी बनता छत्तीसगढ़

नवा रायपुर से शुरू हुई डिजिटल क्रांति, बदल रही प्रदेश की पहचान

डिजिटल भारत के नए दौर में तेजी से एआई और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा छत्तीसगढ़

एक समय था जब छत्तीसगढ़ की पहचान मुख्य रूप से खनिज संपदा, इस्पात उद्योग, ऊर्जा उत्पादन और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई थी। लेकिन बदलते दौर के साथ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ अब एक नई पहचान गढ़ रहा है। यह पहचान है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल नवाचार और भविष्य की तकनीकों की।

दुनिया तेजी से एआई युग में प्रवेश कर रही है। जिस तरह औद्योगिक क्रांति ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को बदला था, उसी तरह आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाज, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और शासन व्यवस्था को नई दिशा दे रहा है। इस वैश्विक परिवर्तन के दौर में छत्तीसगढ़ ने भी भविष्य की इस तकनीकी दौड़ में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है।

नवा रायपुर में विकसित हो रहा एआई आधारित डेटा सेंटर और डिजिटल इकोसिस्टम केवल एक तकनीकी परियोजना नहीं, बल्कि आने वाले दशकों के छत्तीसगढ़ की नई विकास गाथा है। यह पहल प्रदेश को भारत के उभरते हुए टेक्नोलॉजी हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है।

बदल रही है विकास की परिभाषा

आज विकास केवल सड़क, पुल और भवनों तक सीमित नहीं रह गया है। वर्तमान समय में डेटा, डिजिटल कनेक्टिविटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी भी क्षेत्र की प्रगति के सबसे महत्वपूर्ण आधार बन चुके हैं।

जिस प्रकार बीते वर्षों में तेल और ऊर्जा किसी देश की ताकत माने जाते थे, उसी प्रकार आज डेटा और एआई भविष्य की अर्थव्यवस्था का आधार बन चुके हैं।

यही कारण है कि दुनिया के बड़े देश और कंपनियां डेटा सेंटर और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश कर रही हैं। छत्तीसगढ़ ने इस बदलते वैश्विक परिदृश्य को समय रहते समझा और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप डिजिटल अधोसंरचना विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाए। इसका परिणाम यह है कि आज नवा रायपुर देश के सबसे महत्वपूर्ण उभरते डिजिटल केंद्रों में गिना जाने लगा है।

क्यों महत्वपूर्ण हैं डेटा सेंटर?

जब भी हम मोबाइल पर कोई वीडियो देखते हैं, ऑनलाइन भुगतान करते हैं, सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं या एआई आधारित सेवाओं से बातचीत करते हैं, तो उसके पीछे विशाल डेटा सेंटर काम कर रहे होते हैं।

एआई की पूरी दुनिया डेटा पर आधारित है। एआई मॉडल लाखों-करोड़ों जानकारियों का विश्लेषण करते हैं और इसके लिए अत्यधिक क्षमता वाले कंप्यूटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। यही काम डेटा सेंटर करते हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार भविष्य की तकनीकी प्रतिस्पर्धा इस बात पर निर्भर करेगी कि किस देश और राज्य के पास बेहतर डिजिटल अधोसंरचना व अधिक क्षमता वाले डेटा सेंटर हैं।

यही कारण है कि नवा रायपुर में विकसित हो रहा एआई इकोसिस्टम केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

एआई से बदलेगी किसानों की जिंदगी

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा लाभ आम लोगों तक पहुंचने वाला है। विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में इसके प्रभाव दूरगामी होंगे।

एआई आधारित तकनीक किसानों को मौसम संबंधी सटीक जानकारी उपलब्ध करा सकती है। फसलों में बीमारी की पहचान पहले से की जा सकती है। सिंचाई, उर्वरक उपयोग और उत्पादन प्रबंधन को अधिक वैज्ञानिक बनाया जा सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में स्मार्ट एग्रीकल्चर के जरिए किसानों की लागत कम होगी और उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।

छत्तीसगढ़ जैसे कृषि प्रधान राज्य के लिए यह परिवर्तन विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

शिक्षा को मिलेगी नई दिशा

एआई शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव ला रहा है। अब एक ही प्रकार की शिक्षा सभी विद्यार्थियों पर लागू करने के बजाय प्रत्येक छात्र की क्षमता और आवश्यकता के अनुसार सीखने की व्यवस्था विकसित हो रही है।

डिजिटल प्लेटफॉर्म और एआई आधारित लर्निंग सिस्टम छात्रों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना संभव होगा।

छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और आदिवासी अंचलों के विद्यार्थियों के लिए यह तकनीक नई संभावनाओं के द्वार खोल सकती है।

स्वास्थ्य सेवाओं में आएगा बदलाव

एआई स्वास्थ्य क्षेत्र में तेजी से अपनी भूमिका बढ़ा रहा है। मरीजों की जांच, रिपोर्ट विश्लेषण, रोग पहचान और उपचार योजना बनाने में एआई आधारित तकनीक महत्वपूर्ण सहयोग दे रही है।

भविष्य में दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी डिजिटल माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना संभव होगा।

छत्तीसगढ़ के वनांचल और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाने में यह तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

> “ डेटा, डिजिटल कनेक्टिविटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले भारत की नई विकास शक्ति हैं।

युवाओं के लिए अवसरों का नया युग

तकनीकी विशेषज्ञों का मानना है कि एआई क्रांति केवल मशीनों की नहीं, बल्कि रोजगार और कौशल विकास की भी क्रांति है।

आने वाले वर्षों में डेटा साइंटिस्ट, एआई इंजीनियर, मशीन लर्निंग विशेषज्ञ, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल, क्लाउड आर्किटेक्ट, नेटवर्क इंजीनियर और डिजिटल एनालिस्ट जैसे क्षेत्रों में भारी मांग बढ़ने वाली है।

छत्तीसगढ़ के इंजीनियरिंग कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक संस्थान और तकनीकी विश्वविद्यालय अब भविष्य की इन जरूरतों के अनुरूप युवाओं को तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

इससे प्रदेश के हजारों युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार और करियर निर्माण के अवसर प्राप्त होंगे।

गांव से ग्लोबल तक का सफर

इस डिजिटल परिवर्तन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका लाभ केवल महानगरों तक सीमित नहीं रहेगा।

बस्तर, सरगुजा, कांकेर, दंतेवाड़ा, कोरिया, जशपुर और अन्य दूरस्थ क्षेत्रों के युवा भी अब डिजिटल माध्यमों से वैश्विक अवसरों तक पहुंच बना सकेंगे।

रिमोट वर्किंग और डिजिटल सेवाओं के दौर में छत्तीसगढ़ के प्रतिभाशाली युवा अपने राज्य में रहते हुए भी अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं से जुड़ सकेंगे।

निवेशकों की नई पसंद बन रहा है छत्तीसगढ़

बेहतर कनेक्टिविटी, उद्योग-अनुकूल नीतियां, उपलब्ध भूमि, स्थिर ऊर्जा आपूर्ति और तेजी से विकसित हो रहा नवा रायपुर निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है।

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की कई कंपनियां अब छत्तीसगढ़ में तकनीकी निवेश की संभावनाओं का अध्ययन कर रही हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में प्रदेश में डिजिटल सेवाओं, क्लाउड टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण और एआई आधारित उद्योगों में बड़े निवेश देखने को मिल सकते हैं।

हरित तकनीक के साथ विकास

भविष्य का विकास केवल तकनीकी नहीं, बल्कि पर्यावरणीय रूप से भी जिम्मेदार होना चाहिए। इसी सोच के साथ आधुनिक डिजिटल अधोसंरचना को पर्यावरण अनुकूल बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है।

ऊर्जा दक्ष तकनीक, जल संरक्षण, अक्षय ऊर्जा और हरित भवन अवधारणा को प्राथमिकता देकर विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है।

यह मॉडल भविष्य के टिकाऊ विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

AI — नवाचार — भविष्य की तकनीकों का नया केंद्र

DATA — डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर — मजबूत डेटा सेंटर और क्लाउड इकोसिस्टम

SKILL — रोजगार व कौशल — हजारों युवाओं के लिए नए अवसर

FUTURE — नई अर्थव्यवस्था — आत्मनिर्भर और विकसित छत्तीसगढ़ की ओर

नया छत्तीसगढ़, नई पहचान

आज छत्तीसगढ़ एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां परंपरागत संसाधनों की ताकत और आधुनिक तकनीक की क्षमता एक साथ दिखाई दे रही है। राज्य की नई पहचान केवल खनिज, बिजली और उद्योग तक सीमित नहीं रह गई है। अब यह नवाचार, स्टार्टअप, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। नवा रायपुर में विकसित हो रहा एआई इकोसिस्टम आने वाले वर्षों में लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा।

ज्ञान, तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की नई की शक्ति के साथ छत्तीसगढ़ भविष्य के भारत की नई दिशा तय कर रहा है।

संवाद-48873/1

संक्षिप्त समाचार

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने की प्रदेश अध्यक्ष किरण देव से सौजन्य भेंट

रायपुर/नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन गुरुवार को नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ निवास पहुँचकर छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव से सौजन्य भेंट की। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके शीघ्र एवं पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की। छत्तीसगढ़ निवास में आयोजित इस आत्मीय मुलाकात के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन ने प्रदेश अध्यक्ष के उपचार और वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति को लेकर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने चिकित्सकों द्वारा दिए गए परामर्श की जानकारी ली और उनके बेहतर स्वास्थ्य व दीर्घायु जीवन के लिए अपनी शुभकामनाएँ दीं। प्रदेश अध्यक्ष देव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा कुशलक्षेम पूछे जाने और आत्मीय सम्बल प्रदान करने के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर पार्टी के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी, प्रतिनिधि व पारिवारिक सदस्य भी उपस्थित रहे।

डॉ. विमल चोपड़ा होंगे अब भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रभारी

रायपुर। प्रदेश भाजपा ने अपने चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रभारी के पूर्व जारी आदेश को संशोधित कर दिया है। पहले इस पद पर डा.ललित माखीजा को नियुक्त किया गया था अब प्रदेश महामंत्री डा.नवीन मारकंडेय ने आज नियुक्ति का नया आदेश जारी किया है जिसमें प्रदेशाध्यक्ष की अनुशंसा पर महासमुंद के पूर्व विधायक डा.विमल चोपड़ा को भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ का प्रदेश प्रभारी बनाया गया है।

अंजय शुक्ला को मिला राज्यमंत्री का दर्जा

रायपुर। राज्य शासन द्वारा जारी कल के एक आदेश में श्री अंजय शुक्ला, उपाध्यक्ष,छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड, श्री संजय अग्रवाल अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य योग आयोग व शरद अवस्थी उपाध्यक्ष, इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण को राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक राज्य मंत्री का दर्जा केवल शिष्टाचार के लिए प्रदान करता है। उन्हे नियमानुसार सुविधा उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रशासकीय विभाग या आयोग का होगा।

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर कल छत्तीसगढ़ में रहेगा शुष्क दिवस, मदिरा दुकानें रहेंगे बंद

रायपुर। राज्य शासन ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 4 सितंबर को संपूर्ण छत्तीसगढ़ में शुष्क दिवस घोषित किया है। वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कहा गया है। जारी आदेश के अनुसार शुष्क दिवस के दौरान प्रदेश की समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें बंद रहेंगी। इसके साथ ही रेस्टोरेंट बार, होटल-बार, क्लब, अहाता तथा मदिरा बेचने अथवा परोसने वाले सभी प्रकार के लाइसेंसी प्रतिष्ठानों को भी बंद रखा जाएगा। भांग एवं भांगघोटा की फुटकर दुकानें भी इस दिन बंद रहेंगी। शुष्क दिवस की अवधि में मदिरा के व्यक्तिगत भंडारण तथा गैर-लाइसेंसी परिसरों में मदिरा के भंडारण पर भी सख्ती से रोक रहेगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर मदिरा जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

रायपुर-भाटापारा सेक्शन में मजिस्ट्रेट टिकट चेकिंग, 142685 का राजस्व प्राप्त

रायपुर। यात्रियों को टिकट लेकर यात्रा करने हेतु जागरूक करने के उद्देश्य से 1 सितम्बर को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल के स्टेशनों एवं ट्रेनों में रेलवे मजिस्ट्रेट श्री मयंक सोनी के साथ में टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान में मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री राकेश सिंह के साथ में उप मुख्य टिकट निरीक्षक, मुख्य वाणिज्य निरीक्षक (टिकट चेकिंग), 13 टिकट चेकिंग स्टाफ, 4 रेलवे सुरक्षा बल के जवान एवं 06 जीआरपी स्टाफ शामिल थे। यह चेकिंग अभियान 5 ट्रेनों में एवं रायपुर- भाटापारा सेक्शन में चलाया गया। इस मजिस्ट्रेट टिकट चेकिंग अभियान में कुल 250 मामलों से 142685 रुपये बतौर जुर्माना राजस्व प्राप्त हुआ। इसमें बिना टिकट के 109 मामलों से 90500 रूपये एवं अनियमित टिकट के 65 मामलों से 42685 रुपए अनबुक्ड लगेज के 75 मामलों से 8500 रुपए, गंदगी फैलाने वाले 01 मामले से 1000 रूपये राजस्व प्राप्त हुआ।

रायगढ़ की बेटियों ने अंतरराष्ट्रीय खेल मंच पर बढ़ाया देश का मान : वित्त मंत्री चौधरी

रायपुर। वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय लैक्रॉस टूर्नामेंट में भारतीय महिला लैक्रॉस टीम द्वारा कांस्य पदक जीतने पर हर्ष व्यक्त किया है। उन्होंने रायगढ़ जिले की तीन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों सोनम बंजारा, शांति प्रधान और मानसी भूमिया को इस शानदार उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं दी हैं। वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि रायगढ़ की बेटियों ने अंतरराष्ट्रीय खेल मंच पर शानदार प्रदर्शन कर देश और छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है। भारतीय महिला लैक्रॉस टीम ने टूर्नामेंट में बेहतरीन खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए सिंगापुर को पराजित कर कांस्य पदक अपने नाम किया। टीम की इस सफलता में रायगढ़ की तीनों खिलाड़ियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए और अधिक प्रयास जरूरी: राज्यपाल

■ राज्यपाल ने टीम के सदस्यों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर किया सम्मानित

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने कहा कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोडने् के लिए छत्तीसगढ़ में अभी और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। उन्हें गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री सहज रूप से उपलब्ध कराना हम सभी की जिम्मेदारी है। तकनीक के माध्यम से दृष्टिबाधित विद्यार्थियों तक शिक्षा पहुंचाने का वर्ल्ड ऑडियो बुक टीम छत्तीसगढ़ का प्रयास सराहनीय और अनुकरणीय है।

राज्यपाल श्री डेका से आज लोक भवन में वर्ल्ड ऑडियो बुक टीम छत्तीसगढ़ के सदस्यों ने सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल ने टीम के सभी सदस्यों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। टीम की उपलब्धि को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किए जाने पर उन्होंने सभी सदस्यों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

वर्ल्ड ऑडियो बुक टीम द्वारा दृष्टिबाधित एवं सामान्य विद्यार्थियों के लिए 11 हजार से अधिक ऑडियो बुक्स तैयार करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इस अभिनव अभियान की शुरुआत 5 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपति पुरस्कृत शिक्षिका सुश्री के. शारदा के नेतृत्व में हुई। सुश्री शारदा स्वयं अब तक 1,800 से अधिक ऑडियो बुक्स तैयार कर चुकी हैं। उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के 30 शिक्षक-शिक्षिकाएं अपने नियमित शैक्षणिक दायित्वों के साथ इस कार्य में योगदान दे रहे हैं।

राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचना चाहिए। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए ऑडियो के माध्यम से अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयासों को और व्यापक बनाने की जरूरत है, ताकि अधिक से अधिक दृष्टिबाधित विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें।

वर्ल्ड ऑडियो बुक चैनल पर 107 से अधिक प्लेलिस्ट उपलब्ध हैं और इसे अब तक 8 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। टीम द्वारा विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम आधारित एवं उपयोगी अध्ययन सामग्री तैयार की जा रही है। इस अवसर पर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की छत्तीसगढ़ हेड डॉ. सोनल राजेश शर्मा सहित वर्ल्ड ऑडियो बुक टीम के सभी सदस्य उपस्थित थे।

गंगरेल बांध के खुले 3 गेट

रायपुर। धमतरी जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित होने लगा है, वहीं क्षेत्र के सभी प्रमुख जलाशय अब पूरी तरह लबालब हो चुके हैं। कैचमेंट एरिया से हो रही पानी की भारी आवक को देखते हुए जिला प्रशासन के निर्देश पर गंगरेल बांध (रविशंकर सागर जलाशय) के तीन गेट खोल दिए गए हैं, जिनसे कुल 4,670 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसमें से 3,360 क्यूसेक पानी सीधे महानदी में बह रहा है, जबकि 1,410 क्यूसेक पानी रुद्री बैराज के रास्ते मुख्य नहर में प्रवाहित किया जा रहा है। मौसम विभाग द्वारा आगे भी बारिश की संभावना जताए जाने से महानदी का जलस्तर तेजी से बढने् की आशंका है, जिसे देखते हुए कलेक्टर ने तटीय और निचले इलाकों में स्थित गांवों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है।

वर्तमान में जिले के जलाशयों की स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है। मुरूमसिल्ली जलाशय अपनी क्षमता का 98.61 प्रतिशत भर चुका है और उसमें 362 क्यूसेक पानी की आवक बनी हुई है। वहीं गंगरेल जलाशय 97.40 प्रतिशत भरकर 3,365 क्यूसेक आवक दर्ज कर रहा है। इसके अलावा दुधावा जलाशय 86.86 प्रतिशत (437 क्यूसेक आवक) और सोंढूर जलाशय 69.25 प्रतिशत (167 क्यूसेक आवक) तक भर चुके हैं। जलाशयों में लगातार बढ़ते पानी के दबाव को नियंत्रित करने के लिए ही महानदी में जलप्रवाह बढ़ाया गया है।

संजय श्रीवास्तव की अध्यक्षता में नागरिक आपूर्ति निगम के संचालक मण्डल की बैठक संपन्न

■ अनुकंपा नियुक्ति, महंगाई भत्ते में वृद्धि एवं अन्य विषयों पर लिए अहम फैसले

रायपुर। 03 सितंबर को संजय श्रीवास्तव की अध्यक्षता में छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड (नागरिक आपूर्ति निगम) के संचालक मण्डल की 97वीं बैठक मुख्यालय, नवा रायपुर में संपन्न हुई। बैठक में भोसकर विलास संदिपान, प्रबंध संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम, जगदीश सोनकर, विशेष सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, सीताराम तिवारी, उप सचिव (वित्त), मनोज मित्रा, उप सचिव, छ.ग. शासन कृषि विभाग, उपस्थित थे।

बैठक में संचालक मण्डल द्वारा निगम सेवायुक्तो के कार्यकाल अवधि के दौरान निधन उपरांत उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से 03 पात्र अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा जिससे दिवंगत निगम सेवायुक्तों के परिवार के आश्रित सदस्यों को रोजगार के साथ-साथ परिवार के जीवन यापन का जरिया प्राप्त होगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु निगम के आय-व्यय (बजट) से संबंधित प्रासंगिक व्ययों के रूप में प्राप्तियों का अनुमानित बजट राशि रूपये 15116.82 करोड़ का अनुमोदन दिया गया।

निगम में कार्यरत लगभग 800 कर्मियों को वर्तमान सातवां वेतनमान में महंगाई भत्ते में वृद्धि से संचालक मण्डल अवगत हुआ। संचालक मण्डल द्वारा निगम में कार्यरत 105 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 का बोनस स्वीकृति हेतु वित्त विभाग को पत्र भेजे जाने का निर्देश दिया गया । निगम में निक्सी के माध्यम से नियोजित 109 सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामरों के वेतन वृद्धि किये जाने हेतु राज्य शासन को पत्र भेजे जाने का निर्देश दिया गया। छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग द्वारा यात्रा भत्ता से संबंधित जारी आदेश को निगम में यथावत लागू किये जाने का निर्णय लिया गया साथ ही अन्य कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये।

टैंकर से भिड़ी यात्री बस, कोई जनहानि नहीं

रायपुर। गुरुवार की सुबह भाठागांव बस स्टेशन से कवर्धा जाने के लिए निकली सीजी 04 ई 3376 रायपुर ओवरब्रिज पार करके जैसे ही ग्लोबल हॉस्पिटल के सामने पहुंची वह सड़क किनोर खड़ी टैंकर से अनियंत्रित होकर जा भिड़ी। गनीयत यह रही बस में 7 ही यात्री सवार थे और इस दुर्घटना में किसी को चोट नहीं पहुंची वरना बड़ा हादसा हो सकता था। टैंकर से टक्कर होने के बाद बस चालक ने बस को नियंत्रित करने का भरसक प्रयास किया लेकिन वह यात्री बस स्टॉप में जा घुसा और बस स्टॉप का ढांसा क्षतिग्रस्त हो गया वहीं बस के सामने का हिस्सा टूट गया। सूचना मिलते ही डीडीनगर पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

स्व. ओम प्रकाश शर्मा स्मृति में

प्रथम छत्तीसगढ़ राज्य मास्टर्स रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता रायपुर में 13 को

रायपुर। छत्तीसगढ़ टेबल टेनिस संघ की छत्तीसगढ़ वेटरन्स टेबल टेनिस समिति द्वारा 13 सितंबर को स्व. ओम प्रकाश शर्मा स्मृति प्रथम छत्तीसगढ़ राज्य मास्टर्स रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2026 का आयोजन सप्रे शाला टेबल टेनिस हाल, रायपुर में किया जा रहा है जिसमें पुरुष एवं महिला एकल (आयु वर्ग 40, 50, 60, 65, 70, 75) वर्ग हेतु कुल मिलाकर 12 वर्गों में आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में विभिन्न जिलों के पंजीकृत खिलाड़ी ही भाग ले सकेंगे तथा प्रतियोगिता हेतु प्रविष्टि कि अंतिम तिथि 6 सितंबर है।

उक्त प्रतियोगिता के सम्बन्ध में छत्तीसगढ़ टेबल टेनिस संघ के सचिव सार्थक शुक्ला ने जानकारी दी कि प्रतियोगिता में राज्य के सभी जिलों से कुल मिलाकर लगभग 150 पुरुष एवं महिला खिलाडियों के भाग लेने की संभावना है एवं प्रतियोगिता लीग पद्धति में खेली जायेगी जिससे यह सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक खिलाड़ी को कई मैच खेलने का अवसर मिले। यह आयोजन टेबल टेनिस के क्षेत्र में वरिष्ठ खिलाडियों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ राज्य स्तर पर मास्टर्स खिलाडियों के बीच प्रतिस्पर्धा और समरसता बढ़ाने का महत्वपूर्ण प्रयास है।

इस प्रतियोगिता के माध्यम से छत्तीसगढ़ में टेबल टेनिस खेल को और अधिक मजबूत एवं व्यवस्थित बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे अनुभवी खिलाडियों को खेलने का अवसर मिले और युवा खिलाडियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। प्रतियोगिता के दौरान खेल भावना, अनुशासन और उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन को बढ़ावा दिया जाएगा। उपरोक्त जानकारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से प्रतियोगिता के आयोजन सचिव विनय बैसवाड़े ने दी।

आज से 7 दिन बंद रहेगी मांस-मटन की बिक्री

रायपुर। धार्मिक पर्वों और त्योहारों को ध्यान में रखते हुए रायपुर नगर निगम क्षेत्र में सितंबर महीने के 7 दिनों तक मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। नगर निगम के अनुसार 4 सितंबर को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, 7 सितंबर को पर्युषण पर्व के प्रथम दिवस, 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी, 15 सितंबर को पर्युषण पर्व के अंतिम दिवस, 22 सितंबर को डोल ग्यारस, 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी तथा 26 सितंबर को संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा के अवसर पर मांस-मटन की दुकानें और पशुवध गृह बंद रखे जाएंगे।

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध केवल मांस-मटन की दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा। होटल और रेस्टोरेंट में भी मांस-मटन की बिक्री या परोसे जाने की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। प्रतिबंधित दिनों में मांस-मटन बेचते पाए जाने पर संबंधित सामग्री की तत्काल जब्ती की जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रतिबंध का प्रभावी ढंग से पालन कराने के लिए नगर निगम ने अपने मैदानी अमले को भी सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं। जोन स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में मांस-मटन की दुकानों के साथ होटल-रेस्टोरेंट की निगरानी करेंगे। प्रतिबंधित दिनों में दुकानें खुली मिलने या मांस-मटन की बिक्री किए जाने की स्थिति में संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

आज से तीन दिन बंद रह सकते हैं स्कूल-कॉलेज व अन्य संस्थान

रायपुर। छत्तीसगढ़ में 4 सितंबर को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शासकीय अवकाश रहेगा। इस दिन स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। इसके बाद 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और 6 सितंबर को रविवार होने के कारण स्कूल, कॉलेज, बैंक के साथ अन्य संस्थान बंद रहेंगे।

बताया जाता है कि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर प्रदेश में 4 सितंबर को शासकीय अवकाश रहेगा। इसके चलते सरकारी कार्यालयों के साथ-साथ स्कूल और कॉलेज भी बंद रहेंगे। जन्माष्टमी को लेकर प्रदेशभर में धार्मिक आयोजन भी होंगे। विद्यार्थियों और कर्मचारियों के लिए यह छुट्टी सप्ताहांत से जुडने् के कारण खास हो गई है। जन्माष्टमी के अगले दिन यानी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाएगा। यह दिन डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के रूप में मनाया जाता है। हालांकि शिक्षक दिवस पर सभी स्कूलों में अनिवार्य रूप से अवकाश हो, यह जरूरी नहीं है। कई स्कूलों में इस दिन शिक्षक दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। कुछ शिक्षण संस्थानों में स्थानीय व्यवस्था के अनुसार छुट्टी भी हो सकती है। इसके बाद 6 सितंबर को रविवार है। रविवार को स्कूल-कॉलेज समेत अधिकांश सरकारी संस्थानों में साप्ताहिक अवकाश रहता है। इस तरह 4 सितंबर की जन्माष्टमी की छुट्टी, 5 सितंबर की संभावित स्कूल छुट्टी और 6 सितंबर के रविवार को मिलाकर विद्यार्थियों को लगातार तीन दिन छुट्टी मिल सकती है।

रायपुर अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट के शुभारम्भ को लेकर हुई बैठक

रायपुर। रायपुर जिला प्रशासन द्वारा राजधानी शहर रायपुर एवं छत्तीसगढ़ राज्य से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियों, महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों और समाज के लिए उल्लेखनीय योगदान देने वाली हस्तियों को दस्तावेजीकृत करने के उद्देश्य से रायपुर अनफिल्टर्ड नाम से पॉडकास्ट शुरू करने की पहल की जा रही है।

इसी क्रम में पॉडकास्ट के शुभारंभ एवं इसकी रूपरेखा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक रायपुर जिला कलेक्टर डॉ गौरव कुमार सिंह के निर्देशानुसार नगर पालिक निगम रायपुर मुख्यालय में आयोजित की गई।

बैठक रायपुर नगर पालिक निगम के आयुक्त श्री संबित मिश्रा की विशेष उपस्थिति और नगर निगम उपायुक्त डॉ. अंजली शर्मा सहित श्री राहुल कुमार सिंह, श्रीमती अनुराधा दुबे, श्रीमती अर्चना जैन, श्री असीम चंदेल तथा सुश्री निष्ठा जोशी की उपस्थिति रहीं।

बैठक में पॉडकास्ट की संकल्पना, विषय-वस्तु, प्रस्तुति शैली एवं संभावित अतिथियों पर चर्चा की गई। रायपुर अनफिल्टर्ड के माध्यम से रायपुर एवं छत्तीसगढ़ की उन हस्तियों की जीवन यात्राओं, अनुभवों और योगदान को सामने लाया जाएगा, जो हमारे शहर एवं प्रदेश की सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत का अमूल्य हिस्सा हैं। साथ ही रायपुर के विकास, कला-संस्कृति, नागरिक अनुभवों और शहर से जुड़ी अनसुनी कहानियों को भी संवाद के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाएगा।

यूसीसी को लेकर धनेंद्र साहू ने कहा-

समाजों की प्रथाओं से नहीं होनी चाहिए छेड़छाड़

■ जल संरक्षण को लेकर भी सरकार को घेरा

रायपुर। यूसीसी को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने कहा है कि विभिन्न समाजों की अलग-अलग प्रथाएं है, जिस पर प्रहर नहीं होना चाहिए। हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज सब अलग-अलग हैं। यूसीसी में सबसे बड़ी चिंता इसी बात की है। लिव इन रिलेशनशिप समाज के लिए चिंता का विषय हो गया है। इस पर जिम्मेदारी होनी चाहिए, इससे पैदा हुए विभिन्न समस्याओं का हल क्या होगा यह सुनिश्चित होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने समय-समय पर निर्देश दिए हैं। दोनों के बीच सामंजस्य बनाकर सरकार को फैसला करना चाहिए।

मास्टर प्लान को लेकर धनेंद्र साहू ने कहा, 2022 में मास्टर प्लान की तैयारी की गई थी। कई कारणों से सरकार बचना क्यों चाहती है उसको लाया ही नहीं गया। कैपिटल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, यह भी ठंडे बस्ते में है। रायपुर से राजनांदगांव तक मेट्रो चलाने की बात थी, यह भी ठंडे बस्ते में है। कहीं भी इस विषय पर सरकार की सोच नहीं है।

शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव के बयान पर पलटवार करते हुए धनेंद्र साहू ने कहा, सरकार की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ हजारों की संख्या में स्कूल बंद कर रहे हैं। प्रदेश में एक लाख से ज्यादा शिक्षकों के पद रिक्त हैं। सरकार कह रही है 50 हजार शिक्षक भर्ती करेंगे। अभी तक शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। किसी तरह से शिक्षकों की भर्ती नहीं कर रहे हैं और कर भी नहीं पाएंगे।

कांग्रेस के प्रशिक्षण पर बीजेपी के बयान पर धनेंद्र साहू ने कहा, बीजेपी को अपना घर देखना चाहिए। कांग्रेस स्वयं सक्षम है। संगठन सृजन अभियान के तहत नई ऊर्जा झोकी जा रही है। पहले जिलाध्यक्षों का प्रशिक्षण हुआ अब ब्लॉक अध्यक्षों का प्रशिक्षण हो रहा है। इसे देखकर भाजपा घबरा रही है। इससे कांग्रेस काफी मजबूत हो रही है। भाजपा उल्टे सीधे बयान देकर लोगों को हतोत्साहित करने की कोशिश कर रही है।

जल संरक्षण में छत्तीसगढ़ का बेहतर प्रदर्शन, इस पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष साहू ने कहा, यह सब बोगस आंकड़े हैं। सरकार दावा कर रही है तो आंकड़े प्रस्तुत करने चाहिए। कहीं ना एक भी बांध बनाए गए हैं ना कहीं जलाशय बनाए गए हैं। जल संरक्षण नहीं कर रहे, ये लोग नदी को सूखा बनाने का काम कर रहे हैं। जब तक रेत है तब तक पानी है। पर्यावरण खाली कानून बनाकर रखा है कहीं कोई पालन नहीं हो रहा है। चुनौती देने तैयार हूं, सरकार साबित करे कि कहां जल संरक्षण के लिए काम हुआ है।

बीजेपी के पोस्टर पर धनेंद्र साहू ने कहा, बीजेपी को कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता देखकर घबराहट हो रही है। कुछ भी ऊलजलूल आरोप लगाने से नहीं चूक रहे हैं। घोर जातिवादी तो आरएसएस और बीजेपी है। दूसरों को नसीहत देना बंद करें।

कार्यालय-सेनानी, 21वी वाहिनी (भा.र.) छसबल करकाभाट, जिला-बालोद (छ0ग0)

क्र.-21वी वाहिनी/छसबल/करकाभाट/सा.अ./ निविदा-01/I-837-B/2026 दिनांक- 01.09.26.

:: निविदा आमंत्रण सूचना ::

कमांक 2273/निविदा/ग्रा.यां.से./2026-27 बलौदाबाजार, दिनांक 31/08/2026

सेनानी, 21वी वाहिनी (भा.र.) छसबल मुख्यालय करकाभाट, जिला-बालोद (छ0ग0) में पीसीएण्डआर मद के अन्तर्गत निम्नलिखित निर्माण कार्य के लिए सेनानी, 21वीं वाहिनी की ओर से सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से 02 लिफाफा पद्धति में (लिफाफा 'अ' में टेक्निकल बीड एवं लिफाफा 'ब' में फाइनेसियल बीड) निर्माण कार्य बाबत् मोहरबंद निविदायें आमंत्रित की जाती है। सीलबंद लिफाफा के ऊपर निविदा सूचना क्रमांक तथा निविदाकर्ता का पूरा नाम/पता का लेखा किया जाना आवश्यक है।

क्र	कार्य का नाम	अनुमानित राशि (लाख रू. में)	अमानत राशि
01	02 नग साधारण मोर्चा निर्माण कार्य	2.06 लाख	2,060/-
02	100 मी. कंसर्टीना क्वायल फेसिंग कार्य	1.70 लाख	1,700/-
03	बाईक पार्किंग शेड निर्माण कार्य	3.90 लाख	3,900/-
04	वाटर टैंक विथ टायलेट एण्ड बाथरूम ब्लाक निर्माण कार्य	9.45 लाख	9,450/-

01. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि दि. 04.09.26 दि. 17.09.26 के 10:00 बजे से कार्यलयीन समय 17:00 बजे तक

02. निविदा प्रपत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 18.09.2026 के समय 15:00 बजे तक

03. निविदा खोलने की तिथि 18.09.2026 समय शाम 16:00 बजे सभी निविदाकारों की उपस्थिति में खोला जावेगा।

नोटः- निविदा प्राप्त करने हेतु राशि-750/- (रूपये सात सौ पचास मात्र) का चालान 21वी वाहिनी (भा.र.) छसबल करकाभाट-बालोद के नाम से लेखा शीर्ष "0055 पुलिस मिसलिनियस रिसिप्ट" के नाम से स्वीकार्य होगा। निविदा की अन्य जानकारी एवं शर्ते कार्यालय से प्राप्त निविदा फार्म में उपलब्ध करा दी जावेगी।

सेनानी
21 वाहिनी (भा. र.) छसबल
करकाभाट, जिला-बालोद (छ.ग.)

जी-262703088/5

पंजाब चुनाव: भाजपा-अकाली दल के गठबंधन की आहट

राजकुमार सिंह

सीमावर्ती संवेदनशील राज्य पंजाब में विधानसभा चुनाव अगले साल फरवरी में होने हैं, लेकिन राजनीतिक समीकरण अभी से बदलने लगे हैं। पंजाब में भाजपा को बड़ा राजनीतिक खिलाड़ी नहीं माना जाता, लेकिन उसके छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने लगातार दूसरी बार पंजाब विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष पद पर जीत हासिल कर सबको चौंका दिया है। इस जीत का राजनीतिक अर्थ तब और बड़ा हो जाता है, जब पता चले कि पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) का छात्र संगठन दूसरे और सत्ता की प्रबल दावेदार कांग्रेस का छात्र संगठन एनएसयूआई तीसरे स्थान पर रहा। जुलाई में जंतर-मंतर पर 'जेन जी' आंदोलन से बने माहौल के मद्देनजर यह जीत भाजपा के लिए बेहद राहतकारी है। बेशक पिछली बार एबीवीपी ने अकेले दम ही जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार उसे शिरोमणि अकाली दल के छात्र संगठन सोई का समर्थन आगामी विधानसभा चुनाव की बाबत राजनीतिक संकेत भी माना जा रहा है। पिछले दिनों अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में भाजपा-अकाली गठबंधन की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं। मोदी सरकार के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बने परिसीमन विधेयक के समर्थन का ऐलान भी अकाली दल कर चुका है। बेशक भाजपा के संगठन महासचिव बीएल संतोष और पंजाब के प्रभारी बनाए गए सतीश पूनिया सभी 117 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का इरादा दोहरा रहे हैं, लेकिन जमीनी समीकरण बहुत अनुकूल नजर नहीं आता। दशकों तक गठबंधन में रहे भाजपा-अकाली कई बार पंजाब में सरकार बना चुके हैं, लेकिन विवादास्पद कृषि कानूनों के विरुद्ध लंबे चले किसान आंदोलन के चलते दोनों की दोस्ती टूट गई। उन कृषि कानूनों की वापसी के बाद परस्पर विवाद का कोई कारण नहीं बचा। फिर 2022 के पिछले विधानसभा चुनाव में दोनों दल अलग-अलग लड़ कर अपनी-अपनी ताकत भी आंक चुके हैं। अकाली दल मात्र तीन सीट जीत पाया तो भाजपा दो। तब कैप्टन अमरेंद्र सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस और अकाली दल (संयुक्त) के साथ गठबंधन कर भाजपा 73 सीटों पर लड़ी थी। शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन में भाजपा 23 सीटों पर लड़ती रही, जिनमें सबसे ज्यादा 19 उसने 2017 के लोकसभा चुनाव में जीती थीं। बेशक 2024 के लोकसभा चुनाव में बिना कोई सीट जीते ही भाजपा ने मत प्रतिशत में छलांग लगाई, पर सिर्फ उसके बल पर राज्य में सत्ता का सपना साकार नहीं हो सकता। भाजपा का पूरा चुनावी गणित इस बात पर निर्भर नजर आता है कि बहुकोणीय मुकाबले में वह अपना हिंदू वोट बैंक एकजुट रख पाएगी, लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि पंजाब में दूसरी बड़ी ताकत कांग्रेस को भी बड़ी संख्या में हिंदू मत मिलते रहे हैं। दरअसल खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में सिख मतदाताओं पर मजबूत पकड़वाला अकाली दल और खासकर शहरी क्षेत्रों में हिंदू मतदाताओं की पसंद भाजपा मिल कर पंजाब में विजयी समीकरण बनाते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में दोनों के बीच दूरियां बढ़ती गईं। सुखबीर सिंह बादल का शिरोमणि अकाली दल जहां ग्रामीण क्षेत्रों और खासकर सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं भाजपा शहरी क्षेत्रों और खासकर हिंदू समुदाय का। ऐसे में दोनों के बीच गठबंधन की बहाली पंजाब में राजनीतिक के साथ ही सामाजिक एकता को भी मजबूत करेगी।

क्या राजनीतिक दलों से बाहर बन रही नई ताकत, जंतर-मंतर आंदोलन का संदेश भारतीय राजनीति में क्या बदलाव लाएगा?

पी. चिदंबरम

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) द्वारा जंतर-मंतर पर किए गए आंदोलन ने एक ऐसा सबक सिखाया है, जिसे भारतीय लोकतांत्रिक राजनीति के 79 वर्षों में राजनीतिक दल अब तक नहीं सीख पाए हैं। इस 'सबक' की पहली झलक साल के शुरुआत में ही दिखाई दे गई थी, लेकिन उस पर थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे।

इतिहास हमें यही सिखाता आया है कि राजनीतिक दल संघर्ष और चुनाव जीतने के माध्यम से बदलाव ला सकते हैं। यह बात आज भी सही है। क्षेत्रीय दलों ने भी राज्यों में चुनाव जीतकर अपने मुद्दों को मजबूती दी। उदाहरण के लिए, द्रविड़ दलों ने राज्यों की भाषा की सर्वोच्चता, राज्यों के अधिकार, सांस्कृतिक पहचान और भूमि सुधार जैसे मुद्दों को आगे बढ़ाया। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 1975 में चले आंदोलन ने केंद्र की सरकार को बदल दिया और नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संविधान में महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रावधान जोड़े गए। 1978 में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू) के आंदोलन ने सीमा पार से होने वाले प्रवासन को नियंत्रित करने के लिए कानूनी प्रावधानों का रास्ता तैयार किया।

असामान्य योग्यताएं

कॉकरोच जनता पार्टी पारंपरिक अर्थों में कोई राजनीतिक दल नहीं है। इसका जन्म एक व्यक्ति-अभिजीत दिपके-की नाराजगी से हुआ। जाहिर तौर पर, दिपके और उनके कुछ मित्र किसी कथित उकसाने वाली टिप्पणी से बेहद आहत हुए थे। इसके बाद दिपके ने एक मंच बनाया और सवाल उठाया-अगर सारे कॉकरोच एकजुट हो जाएं तो क्या होगा?

उन्होंने घोषणा की कि इस मंच से जुड़ने के लिए व्यक्ति का 'बेरोजगार, आलसी, लगातार ऑनलाइन रहने वाला और पेशेवर अंदाज में लगातार भड़ास निकालने में सक्षम' होना जरूरी है। जाहिर है, ऐसे असामान्य मापदंडों पर खरे उतरने वाले लोगों की कमी नहीं है। इनमें छात्र और शोधार्थी भी हैं। ऐसे कई लोग हैं जो नौकरी करते हैं, लेकिन लगातार ऑनलाइन रहते हैं और पेशेवर अंदाज में अपनी नाराजगी जाहिर करने में माहिर हैं।

जहां तक जानकारी है, इसका कोई औपचारिक संगठन नहीं है, कोई सदस्यता व्यवस्था नहीं है, कोई पंजीकरण नहीं है, न ही कोई घोषित नीतिगत कार्यक्रम या राजनीतिक दल की अन्य पारंपरिक विशेषताएं हैं। इसके बावजूद, 35 दिनों तक चले आंदोलन ने ऐसा असर पैदा किया कि सीजेपी ने दो केंद्रीय मंत्रियों को प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए मजबूर कर दिया, एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, सरकार को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने पड़े और सरकार से लिखित आश्वासन भी हासिल हुआ। यह अपने आप में अभूतपूर्व है।

तमिलनाडु से शुरूआत

जैसा कि मैंने कहा, राजनीतिक दलों से परे और उनके बाहर एक नए तरह की राजनीतिक जगह बनने की पहली आहट 2026 में तमिलनाडु में दिखाई दी। जोसेफ विजय ने फरवरी 2024 में एक राजनीतिक दल-तमिलगा वेट्री कझगम (टीवीके)-बनाने की घोषणा की थी, लेकिन यह पारंपरिक राजनीतिक दल के रूप में विकसित नहीं हुआ। हर तरह से देखें तो यह एक अनौपचारिक और ढीले-ढाले ढंग से संगठित प्रशंसक संघ जैसा ही बना रहा। प्रशंसक संघ के अधिकांश पदाधिकारी ही अलग-अलग स्तरों पर टीवीके के पदाधिकारी बन गए।

टीवीके ने उम्मीदवारों का चयन जाति, धर्म, लिंग, राजनीतिक विरासत, धन-संपत्ति आदि के आधार पर नहीं किया। 234 में से 200 से अधिक उम्मीदवारों के पास न तो चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त धन था और न ही उन्होंने चुनाव प्रचार में पैसा खर्च किया। अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में टीवीके उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार नाममात्र का ही था।

कई उम्मीदवार उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए बिल्कुल अपरिचित थे और उनके पास बूथ एजेंट, मतदान एजेंट या मतगणना एजेंट भी बहुत कम थे। विजय ने कुछ रोड शो किए और उससे भी कम चुनावी सभाओं को संबोधित किया। जाहिर तौर पर मतदाताओं के लिए केवल दो चीजें मायने रखती थीं- 'विजय' और उनका चुनाव चिह्न 'सीटी'। इस पूरे घटनाक्रम में असली जादूगर सोशल मीडिया था- इंस्टाग्राम और यूट्यूब। विजय हर जगह दिखाई दे रहे थे और हर घर में उनकी आवाज पहुंच रही थी।

टीवीके ने डीएमके और एआईएडीएमके जैसी दो बेहद मजबूत राजनीतिक और चुनावी मशीनों के सामने 108 सीटों पर जीत हासिल की और उसे 35 प्रतिशत वोट मिले। किसी भी राजनीतिक दल, किसी नेता, पत्रकार या चुनावी सर्वेक्षक ने टीवीके की जीत की भविष्यवाणी नहीं की थी। जब चुनाव परिणाम आने शुरू हुए तो टीवीके के लिए भी यह उतना ही अप्रत्याशित था, जितना स्थापित राजनीतिक दलों के लिए चौंकाने वाला।

तमिलनाडु के उदाहरण को देखते हुए अब यह कल्पना करना भी असंभव नहीं है कि ऐसे नागरिक, जो एक-दूसरे को जानते तक न हों, आपस में बातचीत न करते हों, किसी संगठन से जुड़े न हों, फिर भी एक ही तरह से मतदान कर सकते हैं और इतने प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं कि वे मिलकर सरकार बना लें।

दलों के लिए चुनौती

राजनीतिक दलों को तमिलनाडु के चुनाव परिणाम और जंतर-मंतर के आंदोलन से निकले निष्कर्षों का गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए। संगठित राजनीतिक दल शायद पूरी तरह अप्रासंगिक न हों, लेकिन 'हाईकमान', कार्यकारिणी समिति, महासभा, सदस्यता और पार्टी के भीतर होने वाले चुनाव जैसी पारंपरिक व्यवस्थाएं भविष्य में अप्रासंगिक हो सकती हैं। राजनीति में इस्तेमाल होने वाला अप्रिय शब्द 'वोट बैंक' भी शायद धीरे-धीरे गायब हो जाए। मोबाइल फोन, ट्विटर (अब एक्स), फेसबुक और इंस्टाग्राम ने नागरिकों को अपनी चुप्पी तोड़ने का साहस दिया है, अब ऐसा लगता है कि उन्होंने डर को भी पीछे छोड़ दिया है। मैं चाहता हूं कि राजनीतिक दलों से परे और उनके बाहर मौजूद यह राजनीतिक क्षेत्र और अधिक विस्तार पाए। जेन-जी और अन्य आंदोलनों से जुड़े युवाओं के सामने अब कई कठिन और चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारियां हैं...

सबसे पहले, उन्हें विश्वविद्यालयों को अंधरूढ़िवादिता से बाहर निकालना होगा।

उन्हें वर्दीधारी पुलिस की बर्बरता, नैतिक पुलिसिंग का सामना करना होगा।

उन्हें कानून के जरिये थोपी जा रही नैतिकता और भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करना होगा।

जेन-जी को स्थानीय राजस्व एवं पंजीकरण कार्यालयों, अस्पतालों, राशन की दुकानों और स्थानीय निकायों में व्याप्त दमनकारी भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए आवाज उठानी होगी।

जंतर-मंतर के आंदोलन के बाद ऐसा लगता है कि बेहतर बदलाव की हर संभावना खुली हुई है।

पुराण दिग्दर्शन ....

विश्व विद्या-निरुपणाध्याय: (दशम अध्याय)

(गतांक से आगे...)

परन्तु दु:ख है कि आज यह विद्या भी लुप्तप्राय: सी हो गई। यदि कुछ मिलती है तो वह इन पुराणों ही में विद्यमान है।

चूर्णनं मूध्नि कांस्यानां मुण्डनं नग्नता तथा।
स्नेहपानावगाहो च रक्तपुष्पानुलेपनम्।।
इत्यधन्यानि स्वप्नानि तेषामकथनं शुभम्।।
(अग्नि पु0 20 226)

अर्थात्- स्वप्न में अपने ऊपर कांसो की चीजों का टूटना, अपने सिर का मुंडना, अपने आपको नंगा-तेल पीता हुआ तथा तेल में स्नान करता हुआ, गले में लाल फूलों की माला पहिने किंवा लाल-चन्दन लगाए देखे तो उस स्वप्न का फल खराब समझो। ऐसे स्वप्नों को दूसरे से न कहना अच्छा है।

शकुन-शास्त्र

एहीति पुरत: शब्द: शस्यते न तु पृष्ठत:।
गच्छेति पश्चाच्छश्योऽग्रच: पुरस्तात्तु विहित:।।
(अग्नि पु0 अ0 230)

अर्थात्--जाते हुवे आदमी को आगे खड़ा हुवा आओ! ऐसा आने को कहे तो अच्छा। यदि पीछे खड़ा बुलावे तो खराब। और जाते हुवे आदमी को यदि कोई पीछे खड़ा कहे कि जाओ! तो अच्छा आगे खड़ा कहे तो बुरा है। शकुनज्ञान के सम्बन्ध में पुराणों में काफी मसाला मिलता है, परन्तु शोक है कि जनता ने पुराणों की उपेक्षा करके इन सब विद्याओं को नष्ट कर लिया है। यदि अब भी यही उदासीन भाव भरा रहा तो रही सही विद्या भी जाती रहेगी।

सामुद्रिक-शास्त्र

यह भी एक चमत्कारिक विद्या है जिसके द्वारा स्त्री पुरुष की रेखा आदि शरीर-लक्षणों से ही उसकी जीवन-घटनाओं पर प्रकाश डाला जा सकता है। इस शास्त्र का प्राय: लोप सा हो चला है। जिनको इस विद्या का यत्किंचित् भी ज्ञान है।

क्रमश:...

भगवान कृष्ण, जो गिरिधर भी हैं और मुरलीधर भी

कृष्ण प्रताप सिंह

योगेश्वर, लीलाधर, संपूर्ण पुरुष, माखनचोर, चितचोर, रास रचैया और।।। भगवान श्रीकृष्ण के भक्त उनके लिए ऐसे अनेक संबोधनों का प्रयोग करते हैं। दूसरी ओर दार्शनिक चर्चाओं में इस बात को अलग से और खास तौर पर रेखांकित किया जाता है कि समाजवादी चिंतक डॉ। राममनोहर लोहिया ने अपने लब्धप्रतिष्ठ निबंध 'राम, कृष्ण और शिव' में उन्हें राम व शिव के साथ भारत में पूर्णता के तीन महान स्?वप्नों में से एक बताया है। साथ ही कहा है कि भले ही ये तीनों स्वप्न ऊपर से एक-दूसरे से अलग दिखते हैं, इनमें इस देश के रंग, सपने और उदासी एक साथ झलकते हैं।

इसी निबंध में उन्होंने आगे लिखा है कि कृष्ण ने लगातार मनुष्य बनने की कोशिशें कीं और 'संपूर्ण पुरुष' बने। भगवान होते हुए भी वे हर पल एक साधारण और जीवंत मनुष्य की तरह पेश आए। विकट से विकट परिस्थितियों में भी उनके चेहरे पर मुस्कान व आनंद बने रहे। वे कभी जीवन से भागे नहीं और हर परिस्थिति का हंसते हुए अपनी खास तरह की कूटनीतिक दूरदर्शिता से सामना किया।

इतना ही नहीं, जीवन के विरोधाभासों को भी आनंदपूर्वक नायकसुलभ गहराई से जिया। ऐसे में स्वाभाविक ही है कि उनके नायकत्व में आश्वस्त जनमानस उनके जीवन-दर्शन को उनकी लीलाएं माने और लीलाओं के अगणित व असीम होने के कारण उन्हें लीलाधर कहे। कवि रहीम तो अपने एक दोहे में यह तक कह गए हैं कि गिरिधर (यानी एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाने में समर्थ) होने के बावजूद कोई उन्हें कोमलगात समझे व मुरलीधर कहे तो भी वे 'कछु दुख मानत नाहिं।'

इसलिए कि उनके निकट उनके जीवन को पूर्णता की ओर ले जाने में जितना योगदान उनके गिरिधर होने का है, उतना ही मुरलीधर होने का भी। बल्कि कुछ मायनों में मुरलीधर होने का कुछ ज्यादा ही योगदान है। निस्संदेह, कई-कई युद्धों से आक्रांत व अशांत दुनिया के इन दिनों के हालात में उनको गिरिधर बनाने वाली गोवर्धनलीला की प्रेरणाएं हमारे ज्यादा काम की हैं क्योंकि वे अन्यायी व दमनकारी सत्ताधीशों के साथ अंधविश्वासों के भी प्रतिरोध की सीख देती हैं।

इस लीला में किया गया देवताओं के राजा इंद्र का प्रतिरोध हमारी परंपरा का अब तक का 'सबसे क्रांतिकारी कदम' बताया जाता है। अकारण नहीं कि अनेक कृष्ण भक्त इस लीला को दमनकारी सत्ताओं और अंधविश्वासों के खिलाफ एक बहुत बड़ा वैचारिक और सामाजिक विद्रोह मानते हैं।

पुराणों के अनुसार गोवर्धन लीला से पहले ब्रजमंडल के निवासी देवताओं के राजा इंद्र के कोप के डर के मारे उनकी पूजा किया करते थे। श्रीकृष्ण ने इस भय-आधारित पूजा को सीधी चुनौती दी और कहा कि पूजा तभी सच्ची पूजा कहलाती है, जब भयवश नहीं, बल्कि कृतज्ञता के भाव से की जाए। साथ ही उन्होंने उनको समझाया कि उनका जीवन गोधन, वनों और गोवर्धन पर्वत पर निर्भर है, इसलिए उनको गोवर्धन की पूजा शुरू करनी चाहिए। गोवर्धन की यह पूजा वास्तव में प्रकृति व पर्यावरण की पूजा का पर्याय थी।

पश्चिम एशिया में बदलते सुरक्षा समीकरण और भारत की चुनौती

श्याम सरन

सऊदी अरब, तुर्किये और पाकिस्तान ने गत 7 अगस्त को सऊदी अरब के पवित्र इस्लामी शहर मक्का में एक संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का पूरा पाठ सार्वजनिक नहीं किया गया है इसलिए विश्लेषण उस संयुक्त बयान पर आधारित है जो हस्ताक्षर के बाद जारी किया गया। समझौते में यह प्रावधान है कि किसी एक सदस्य देश पर सशस्त्र हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। इसके अलावा यह तीनों देशों को संयुक्त रक्षा निर्माण, क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ाने और सामूहिक प्रतिरोध को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध करता है।

तीनों देशों की ओर से जो टिप्पणियां की जा रही हैं उनमें से ज्यादातर में जोर दिया गया है कि यह समझौता तुर्किये की सैन्य औद्योगिक क्षमता, सऊदी अरब की वित्तीय ताकत और पाकिस्तान की परमाणु क्षमता को एक साथ लाता है जिससे एक प्रभावी प्रतिरोधक शक्ति तैयार होती है। तीनों देशों ने स्पष्ट किया है कि यह समझौता किसी खास देश के खिलाफ नहीं है बल्कि इसका उद्देश्य सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता उपलब्ध कराना है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यदि किसी एक साझेदार के मामले में यह प्रतिरोधक क्षमता विफल हो जाती है तो बाकी दोनों देश किस तरह प्रतिक्रिया देंगे।

यह घोषणा भी की गई है कि मक्का संधि का मुख्यालय सऊदी अरब के रियाद में होगा लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि इसमें नाटो जैसी संयुक्त संचालन कमान या युद्ध की स्पष्ट रणनीति और सिद्धांत मौजूद है। तीनों देशों के सुरक्षा खतरे अलग-अलग हैं। पाकिस्तान के लिए यह भारत है, सऊदी अरब के लिए ईरान और अब इजरायल हैं। तुर्किये के लिए यह इजरायल और सीरिया तथा दक्षिणी लेबनान पर प्रभुत्व कायम करने की उसकी कोशिश हो सकती है।

इन अलग-अलग सुरक्षा संबंधी धारणाओं के कारण सामूहिक रक्षा की कोई भी व्यवस्था जटिल और समस्यापूर्ण हो जाती है। लेकिन इसमें कोई

संदेह नहीं कि यह समझौता पश्चिम एशिया में सुरक्षा समीकरणों के एक महत्त्वपूर्ण पुनर्गठन का संकेत देता है। इसका संदर्भ इस समय चल रहे ईरान युद्ध और क्षेत्र में इजरायली सैन्य आक्रामकता के विस्तार से जुड़ा है जो गाजा युद्ध से आगे बढ़ चुकी है। इसके पीछे सबसे बड़ी वास्तविकता अमेरिका की घटती सैन्य क्षमता और खाड़ी के अपने सहयोगियों को लंबे समय से दिए जा रहे सुरक्षा आश्वासनों को कायम रखने में उसकी विफलता है। खबर है कि मिस्र भी इस समझौते में शामिल हो सकता है जिससे यह और प्रभावी हो जाएगा। तुर्किये और पाकिस्तान दो किनारों की तरह हैं जिनके बीच सऊदी अरब एक रणनीतिक रूप से बेहद महत्त्वपूर्ण स्थान पर स्थित है। एक ओर लाल सागर है और दूसरी ओर होर्मुज स्ट्रेट। तेल समृद्ध देश के रूप में सऊदी अरब की आर्थिक समृद्धि इन समुद्री मार्गों तक सुरक्षित पहुंच पर निर्भर करती है।

मक्का संधि से पहले 14 देशों का एक समुद्री गठबंधन बनाया गया था। इसकी शुरुआत सऊदी अरब ने 30 जुलाई को की थी। इसका उद्देश्य वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा करना, ऊर्जा आपूर्ति के मार्गों को सुरक्षित रखना और लाल सागर, अदन की खाड़ी तथा बाब-अल-मंदेब स्ट्रेट में व्यापारिक मार्गों को खुला रखना था। इसमें होर्मुज स्ट्रेट को शामिल नहीं किया गया था। तुर्किये और पाकिस्तान इस गठबंधन के सदस्य हैं। जहां तक जानकारी है भारत को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था। इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान ने 17 सितंबर 2025 को द्विपक्षीय सामरिक पारस्परिक रक्षा समझौते को सार्वजनिक किया था। इसमें भी एक प्रावधान है जिसके तहत दोनों देश इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि किसी एक पक्ष पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। बाद में हुए त्रिपक्षीय मक्का समझौते में भी यही प्रावधान शामिल किया गया। द्विपक्षीय समझौते की घोषणा कतर पर इजरायल के हवाई हमले के बाद हुई थी। उस समय कुछ हमास नेता गाजा में शांति स्थापित करने के लिए कतर द्वारा किए जा रहे मध्यस्थता प्रयासों के सिलसिले में वहां मौजूद थे। यह हमला सऊदी अरब समेत खाड़ी देशों के लिए एक बड़ा झटका था।

यहां भी समझौते का पूरा पाठ सार्वजनिक नहीं किया गया है। लेकिन घटनाक्रम से संकेत मिलता है कि इजरायली आक्रामकता का खतरा भी इन हालिया समझौतों को आगे बढ़ाने वाला उतना ही महत्त्वपूर्ण कारण है जितना ईरान से उत्पन्न खतरा। अमेरिका ने मक्का समझौते का स्वागत किया है और इसे जिम्मेदारियों के बंटवारे तथा अपने सहयोगियों और साझेदारों द्वारा अपनी रक्षा की अधिक जिम्मेदारी खुद उठाने के एक सकारात्मक उदाहरण के रूप में देखा है। अमेरिका इन देशों का एक अपरिहार्य रक्षा साझेदार बना रहेगा।

तुर्किये नाटो का सदस्य और सहयोगी है। पाकिस्तान गैर-नाटो प्रमुख सहयोगी है और अमेरिका का सऊदी अरब के साथ द्विपक्षीय सुरक्षा गठबंधन है। हालांकि अगर इन साझेदार देशों के लिए इजरायल ही निशाना बनता है तो अमेरिका का रुख अलग हो सकता है। आधिकारिक बयान में ईरान ने मक्का समझौते की आलोचना करने से परहेज किया है लेकिन इस बात पर जोर दिया है कि इस्लामी देशों को क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए आपस में सहयोग करना चाहिए और बाहरी शक्तियों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यह ईरान की रणनीतिक चाल है क्योंकि वह खाड़ी में अमेरिकी मौजूदगी कम होने का स्वागत करेगा। मक्का समझौते के पीछे तीन घटनाक्रम महत्त्वपूर्ण हैं। पहला, खाड़ी में अपने सहयोगी देशों को दी जाने वाली अमेरिकी सुरक्षा गारंटियों की विश्वसनीयता में कमी और ईरान पर प्रभावी ढंग से काबू पाने में अमेरिका की असमर्थता। दूसरा, सऊदी अरब और तुर्किये के बीच चली आ रही प्रतिद्वंद्विता और यहां तक कि परस्पर विरोध की भावना का खत्म होकर दोनों के बीच सैन्य गठबंधन में बदल जाना। यह क्षेत्र में हुआ अधिक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव है। तीसरा, तुर्किये और सऊदी अरब दोनों के साथ लंबे समय से द्विपक्षीय सैन्य संबंध रखने वाले देश के रूप में पाकिस्तान ने उनके बीच एक भरोसेमंद सेतु की महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह समझौता पाकिस्तान की भूराजनीतिक स्थिति और क्षेत्र में उसकी भूमिका को मजबूत करता है। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इस समझौते को अमेरिका का समर्थन प्राप्त है।

चीन इस बदलते हुए भू-राजनीतिक समीकरण में अब तक बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दिया है, जबकि इस क्षेत्र में उसके महत्त्वपूर्ण आर्थिक, ऊर्जा और सुरक्षा संबंधी हित हैं। क्षेत्र में पाकिस्तान की बढ़ती हैसियत और प्रभाव का लाभ चीन, पाकिस्तान के साथ अपनी गहरी सुरक्षा साझेदारी के जरिये उठा सकता है। जब इस क्षेत्र में एक नई सुरक्षा व्यवस्था आकार लेने लगेगी जिसमें ईरान की भागीदारी भी जरूरी होगी तो चीन एक बार फिर सुविधाकर्ता की भूमिका निभा सकता है। अतीत में भी उसने ईरान और सऊदी अरब के बीच समझ कायम कराने में मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। चीन अब अमेरिका द्वारा छोड़ी गई खाली जगहों को भरने की कोशिश करेगा।

भारत के पास इस घटनाक्रम में गहरी रुचि रखने के पर्याप्त कारण हैं। खाड़ी देशों में रहने और काम करने वाले 90 लाख भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण सर्वोच्च चिंता का विषय है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा भी इस क्षेत्र से गहराई से जुड़ी हुई है क्योंकि उसके तेल और गैस की आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।

आज का इतिहास

1665 मुग़लों और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच राजा जयसिंह संधि पर हस्ताक्षर हुए।
1781 स्पेन के निवासियों द्वारा लॉस एंजिल्स की स्थापना की गयी।
1888 गांधीजी ने इंग्लैंड के लिए समुद्री यात्रा शुरू की।
1944 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सैनिकों ने बेल्जियम के एंटवर्प शहर में प्रवेश किया।
1946 भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया गया।
1967 6.5 तीव्रता वाले भूकंप की चपेट में आया महाराष्ट्र का कोयना बांध, 200 से ज्यादा लोगों की मौत।
1969 उत्तरी वियतनाम के राष्ट्रपति एवं राष्ट्रपिता हो ची मिन्ह का देहावसान।
1985 73 सालों के बाद समुद्र में डूबे जहाज टाइटेनिक की तस्वीरें सामने आई थीं। टाइटेनिक दुर्घटना में इस जहाज पर सवार 1,500 लोग मारे गए थे।
1998 अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने आयरलैंड के डबलिन में स्वीकार किया कि मोनिका लेविंस्की के साथ सम्बन्ध क़ायम करना बड़ी ग़लती थी।
1998 डरबन में 12वें गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन सम्पन्न।
1998 लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पी.एच.डी करने के दौरान इसे विकसित किया था।
1999 ईस्ट तिमोर में सम्पन्न हुए जनमत संग्रह में 78.5 प्रतिशत जनता ने इंडोनेशिया से स्वतंत्रता के पक्ष में अपना मत प्रकट किया।
2000 श्रीलंका के उत्तरी जाफना के बाहरी सीमाओं पर श्रीलंका सेना तथा मुक्ति चीते के बीच हुए संघर्ष में 316 लोग मारे गये।
2001 श्रीलंका ने मुशर्रफ़ से सैन्य मदद मांगने का फैसला किया।
2005 लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन करते नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला गिरफ़्तार।
2006 ऑस्ट्रेलिया के मशहूर टीवी पर्सनैलिटी और पर्यावरणविद स्टीव इरविन का एक समुद्री मछली %स्टिंगरे% के काटने से निधन।
2007 ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अकबर हाशमी रफ़संजानी को ईरान की सर्वोच्च धार्मिक संस्था का प्रमुख चुना गया।
2008 मायावती सरकार ने उत्तर प्रदेश संगठित अपराध विरोधी क़ानून (यूपीकोका) विधेयक-2007 को तत्काल प्रभाव से वापस करने का निर्णय किया।
2008 केन्द्रीय कैबिनेट ने सात राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के सम्बन्ध में परिसीमन आयोग की सिफारिशों में सुधार के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी।
2009 गुजरात उच्च न्यायालय ने असवंत सिंह की मुहम्मद अली जिन्ना पर लिखी गई किताब पर गुजरात में लगे प्रतिबंध को हटाया।

सीजेपी प्रोटेस्ट क्यों हुआ कैंसिल, पीएम मोदी से इसका क्या है कनेक्शन?

अभिनय आकाश

नीट-यूजी पेपर लीक के विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ दर्ज मामलों को जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए रद्द किया, तब अदालत कक्ष में भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के बीच एक-दूसरे की सराहना देखने को मिली। यह पार्टी मुख्य न्यायाधीश की एक टिप्पणी के व्यंग्यात्मक जवाब के रूप में अस्तित्व में आई थी। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने यह फैसला दिल्ली पुलिस और चार राज्य सरकारों द्वारा शीर्ष अदालत से संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिली विशेष शक्तियों का उपयोग करने की अपील के बाद सुनाया। केंद्र सरकार पर केस वापस लेने के वादे से मुकरने का आरोप लगाते हुए सीजेपी ने 5 सितंबर को एक मार्च निकालने का ऐलान किया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आने के बाद इस विरोध प्रदर्शन को वापस ले लिया गया। क्यों सीजेपी ऐन मौके पर पीछे हट गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिक्चर में आ गए। बीजेपी के पीछे हटने का मतलब यह कि उन्होंने 5 सितंबर का अपना विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया है। पर जो वजह बताई जा रही है असली बात वही है या फिर कहानी में कुछ ट्विस्ट भी है। सीजेपी का प्रोग्राम था, तारीख भी तय हो चुकी थी। 5 सितंबर की। पर फिर कहानी में यू टर्न आ गया। केंद्र सरकार पीछे हटी तो कॉकरोच जनता पार्टी वाले भी। सीजेपी वालों ने ऐलान किया 5 सितंबर को अब कोई विरोध प्रदर्शन नहीं होगा। बस इसके कुछ ही देर बाद सीन में एंट्री हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। उन्होंने वर्टिकल में कोई इंस्टा पर रील नहीं डाला है। बच्चों से कोई अपील भी नहीं की है। बीजेपी के अंदर से जो खबर आई है वो यह है कि प्रधानमंत्री जेन जी से संवाद करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस पर दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ़ कॉमर्स (एसआरसीसी) जाने की संभावना है। यह दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि एसआरसीसी अपने 100 साल पूरे कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मोदी के कॉलेज के शताब्दी समारोह में शामिल होने और छात्रों से बातचीत करने की उम्मीद है। इस प्रस्तावित दौरे का एक अहम हिस्सा मोदी और जेन-जी छात्रों के बीच सीधी बातचीत हो सकती है। इस सेशन से छात्रों को प्रधानमंत्री के साथ अपने विचार, उम्मीदें और चिंताएं साझा करने का मौका मिलने की संभावना है। यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब भाजपा जेन-जी तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। पार्टी युवाओं से जुड़ने और वोटरों की अगली पीढ़ी के साथ बातचीत को मज़बूत करने के लिए एक खास रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी ने हाल ही में जेन ज़ेड तक

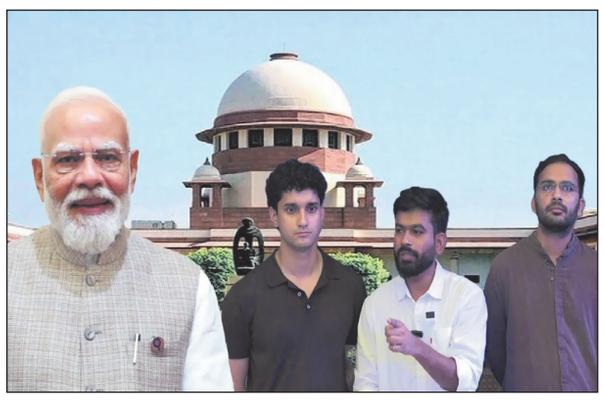

पहुँचने के अपने कार्यक्रम के लिए एक टीम बनाई है। इसका मकसद सीनियर नेताओं और युवा प्रतिनिधियों को एक साथ लाना है। इस पहल का उद्देश्य युवा भारतीयों की उम्मीदों को समझना और बातचीत व भागीदारी के लिए और मौके बनाना है। उम्मीद है कि पार्टी युवाओं के साथ बातचीत को केवल पारंपरिक राजनीतिक कार्यक्रमों तक सीमित रखने के बजाय, सीधे जुड़ने और बातचीत करने पर ध्यान देगी।

एचटी की पिछली रिपोर्ट के अनुसार, बीजेपी ने जेन ज़ी तक पहुँचने के लिए एक खास टीम बनाई है। पार्टी नेताओं ने छोटी सभाओं, कैंपस प्रोग्राम और सीधे बातचीत के ज़रिए युवाओं को जोड़ने के तरीकों पर चर्चा की। अगस्त में, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने लोगों तक पहुँचने की योजना पर एक बैठक की। इसमें नेताओं ने कहा कि युवाओं को जोड़ने का काम लगातार चलना चाहिए, न कि यह सिर्फ़ बड़े राजनीतिक कार्यक्रमों तक ही सीमित रहे। पार्टी की युवा रणनीति पर चर्चा के लिए अहम राज्यों जैसे चुनाव वाले उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के करीब 45 नेताओं को भी शामिल किया गया। पार्टी युवाओं के लिए एक अभियान की भी योजना बना रही है, जिसमें बाइक यात्रा, हैकाथॉन, मैराथन, साइकिलिंग इवेंट और इनोवेशन चैलेंज जैसी गतिविधियाँ शामिल होंगी। बीजेपी की युवा शाखा 17 सितंबर को वडनगर-वाराणसी मोटरसाइकिल यात्रा शुरू करने वाली है। पार्टी के सेवा पखवाड़ा में स्कूली छात्रों, कॉलेज जाने वाले युवाओं, पोस्ट-ग्रेजुएट स्कॉलर्स और युवा इनोवेटर्स के लिए कार्यक्रम शामिल होंगे।

पिछले महीने, नीट विवाद को लेकर युवाओं के विरोध-प्रदर्शनों ने सरकार को हिलाकर रख दिया था और आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा। बाद में प्रधान ने कहा कि विरोध-प्रदर्शनों के दौरान जेन-जी को गुमराह करने की कोशिशें की गई थीं। इन विरोध-प्रदर्शनों में हज़ारों युवा सड़कों पर उतर आए। छात्रों और युवा संगठनों ने पेपर लीक, छात्रों की आत्महत्या और परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ियों को लेकर जवाबदेही की मांग की। विरोध-प्रदर्शनों के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की आवाज़ भी प्रमुखता से सुनाई दी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि इन विरोध-प्रदर्शनों से बीजेपी की छवि को नुकसान पहुंचा है और विपक्षी पार्टियों को यह समझना चाहिए कि युवा सीजेपी जैसे समूहों की ओर क्यों आकर्षित हुए। शिक्षा मंत्रालय छोड़ने के बाद, प्रधान ने अगस्त में कहा था कि नीट विरोध-प्रदर्शनों के दौरान कुछ लोगों ने जेन ज़ी को गुमराह करने की कोशिश की थी। उन्होंने इस विवाद के चलते अपना इस्तीफ़ा देने के फ़ैसले का भी बचाव किया।

5 सितंबर से फिर आंदोलन शुरू करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी ने अब अपने हाथ पीछे खींच लिए। तो सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई थी। इस बात पर कि स्टूडेंट प्रदर्शन को लेकर देश भर में दर्ज एफआईआर का क्या होगा? सीजीपी की शुरुआत से यह मांग थी कि एक छात्र के खिलाफ भी कारवाई नहीं होनी चाहिए। मोदी सरकार और बीजेपी के लोगों के बीच जिन कुछ बिंदुओं पर सहमति बनी थी और जंतरमंतर वाला प्रोटेस्ट वापस हुआ था उनमें से एक तो यही था। तो देश की सबसे बड़ी अदालत में जब यह मामला गूंजा तो वहां सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच हुए छात्र प्रदर्शनों के संबंध में किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज एफआईआर पर आगे कारवाई या जांच नहीं होगी। इन सभी एफआईआर को हर मकसद के लिए बंद माना जाएगा। इसके बाद 5 सितंबर को होने वाले विरोध मार्च को वापस लेने की बात सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कह दी कि सितंबर 5 को जो हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च था इंडिया गेट से न्यू पुलिस हेड क्वार्टर्स तक वो हम लोग कॉल ऑफ कर रहे हैं क्योंकि हमारे सारे डिमांड्स सरकार ने मान लिया

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तीन जजों की बेंच कर रही है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत के अलावा बेंच में जस्टिस जॉय मौल्या बागची और जस्टिस बी मोहना भी शामिल है। भारत सरकार का पक्ष रख रहे हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। मेहता ने अदालत में कहा कि सिर्फ दिल्ली पुलिस के मामले में केंद्र सरकार ही ने नहीं बल्कि बिहार, असम, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर दर्ज सभी एफआईआर रद्द करने की बात मान ली है। बच्चों के लिए हम कितना सोचते हैं। उनका दुख मेरा दुख है। यह अदालत में भी सरकार बता चुकी थी।

'खगांतक-243': परीक्षण सफल होते ही चीन, पाकिस्तान की बढ़ी टेंशन

नीरज कुमार दुबे

दुश्मनों पर अब आसमान से कहर बरपाने की भारत की ताकत और बढ़ गई है। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम 'खगांतक-243' का सफल परीक्षण किया है। 140 किलोमीटर से अधिक दूरी तक मार करने में सक्षम यह हथियार भारतीय लड़ाकू विमानों को दुश्मन के ठिकानों पर दूर से ही सटीक और घातक हमला करने की क्षमता देगा। भारतीय वायुसेना ने इस उपलब्धि को "Precision. Power. Pride" बताते हुए कहा है कि परीक्षण ने सभी निर्धारित उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। आईएएफ के मुताबिक, यह भारतीय वायुसेना और भारतीय रक्षा उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया तथा रक्षा नवाचार के जरिए देश की मारक क्षमता को नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाला कदम है। हम आपको बता दें कि खगांतक-243 एक 300 किलोग्राम श्रेणी का एयरबोर्न लॉन्ग रेंज स्टैंड-ऑफ प्रिसिजन गाइडेड ग्लाइड बम है। इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि लड़ाकू विमान को लक्ष्य के ठीक ऊपर पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विमान सुरक्षित दूरी से इस हथियार को छोड़ सकता है और इसके बाद बम अपने पंखों और नियंत्रण सतहों की मदद से लक्ष्य की ओर ग्लाइड करेगा। यानी युद्ध की स्थिति में भारतीय लड़ाकू विमान दुश्मन के मजबूत एयर डिफेंस क्षेत्र में गहराई तक घुसने के जोखिम को कम करते हुए दूर से हमला कर सकते हैं। यही आधुनिक हवाई युद्ध की सबसे बड़ी जरूरत है। यानि दुश्मन पर हमला करो, लेकिन उसकी जवाबी मार की सीमा से बाहर रहो। रिपोर्टों के मुताबिक, करीब 12,000 मीटर की ऊंचाई से छोड़े जाने पर खगांतक-243 की रेंज 140 किलोमीटर से अधिक हो सकती है। इसका डिजाइन भी खास है। इसमें एक बेलनाकार बॉडी, बीच में घूमने वाले ग्लाइड विंग और पीछे पांच नियंत्रण सतहें हैं, जो इसे लक्ष्य की दिशा में नियंत्रित करने में मदद करती हैं। खगांतक-243 में एमके 81 जनरल-पर्पज ब्लास्ट-फ्रैगमेंटेशन वारहेड लगाया गया है, जिसमें करीब 125 किलोग्राम विस्फोटक भराव है। यह संयोजन इसे महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों, संरचनाओं और अन्य लक्ष्यों के खिलाफ प्रभावी हथियार बना सकता है। इस हथियार श्रेणी की एक और महत्वपूर्ण विशेषता इसका मॉड्यूलर डिजाइन है। यानी भविष्य में मिशन की जरूरत और ग्राहक की मांग के अनुसार अलग-अलग वारहेड और गाइडेंस कॉन्फिगरेशन विकसित किए जा सकते हैं। यही लचीलापन खगांतक श्रेणी को केवल एक हथियार नहीं, बल्कि भविष्य में विकसित होने वाली एक व्यापक प्रिसिजन स्ट्राइक क्षमता का आधार बना सकता है। साथ ही खगांतक-243 भारत के रक्षा उद्योग की साझेदारी का भी उदाहरण है। इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (भेल) और JSR Dynamics ने मिलकर विकसित किया है। JSR Dynamics ने बम की बॉडी और नियंत्रण प्रणाली विकसित की है, जबकि भेल ने इलेक्ट्रॉनिक्स और गाइडेंस सबसिस्टम उपलब्ध कराए हैं। भारतीय वायुसेना पहले ही भेल को खगांतक-243 म्यूनिशन के लिए ऑर्डर दे चुकी है, हालांकि ऑर्डर की संख्या और अनुबंध की कीमत सार्वजनिक नहीं की गई है। इसका प्रारंभिक फ्लाइट टेस्ट प्लेटफॉर्म एसयू-30एकेआई है और भविष्य में इसे वायुसेना के अन्य विमानों के साथ भी एकीकृत किए जाने की संभावना है। यहां एक सवाल उठता है कि क्या चीन और पाकिस्तान के पास भी ऐसे हथियार हैं? इस सवाल का जवाब हां है लेकिन यह भी उल्लेखनीय है कि चीन और पाकिस्तान के पास मौजूद ऐसे हथियारों की अपेक्षा भारत के हथियार गुणवत्ता और मारक क्षमता में कहीं आगे हैं।

तुर्किये-पाकिस्तान-सऊदी अरब मक्का रक्षा समझौता

राजेश बादल

तुर्किये और सऊदी अरब के साथ मक्का रक्षा समझौते (एमडीए) से पाकिस्तान गदगद है। वह खुश है कि संगठन भारत के खिलाफ रक्षा कवच का काम करेगा। अगली कड़ी के रूप में बांग्लादेश और मिस्र को संगठन का सदस्य बनाने की पहल की जाएगी। सूत्र वाक्य यह है कि एक मुल्क पर हमला तीनों देशों पर आक्रमण माना जाएगा।

कमोबेश नाटो की तर्ज पर गठित इस एमडीए के पीछे जाहिरा तौर पर तो इजराइल-अमेरिका और ईरान के बीच जंग को नए संगठन का आधार माना जा रहा है, मगर परदे के पीछे के कारण कुछ और ही हैं। संगठन के तीनों सदस्य सुन्नी बाहुल्य हैं और वे शियाओं से दूरी बनाए रखना चाहते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से वे अमेरिका के इशारे पर इस संगठन के लिए बाध्य हुए हैं।

इसलिए भारत के लिए कम, ईरान के लिए यह ज्यादा चिंता का विषय हो सकता है। बहुत संभव है कि आगे जाकर यह हाथी का दांत साबित हो जाए, क्योंकि अभी तक मजहबी धुरी पर बने संगठन बहुत कारगर साबित नहीं हुए हैं। एक नजर अतीत पर डालें तो धार्मिक नजरिये से विश्लेषण में आसानी हो जाएगी। करीब 76 साल पहले अरब लीग के देशों ने सामूहिक सुरक्षा और आर्थिक नजरिये से संगठन बनाया।

तब पाकिस्तान को खालिस मुस्लिम देश नहीं माना गया था। लेकिन अलग-अलग मुल्कों में अलग-अलग राजनीतिक नेतृत्व, उनके विरोधाभासों तथा सैनिक समन्वय में भरोसे की कमी के चलते संगठन ने दम तोड़ दिया। इसके पांच साल बाद बगदाद संधि के जरिये इराक, ईरान, पाकिस्तान, ब्रिटेन और तुर्की एकजुट हुए। उस समय इसका मकसद सोवियत संघ की विस्तारवादी नीतियों से अपने को बचाने का था।

लेकिन 1958 में इराक में फौजी तख्तापलट और 1979 में ईरानी क्रांति से यह एकजुटता बिखर गई। फिर पांच साल बाद खाड़ी सहयोग परिषद बनी। इस संगठन को पेनिनसुला शील्ड फोर्स नाम दिया गया। उन दिनों ईरान-इराक जंग चल रही थी।यह जंग 1980 से 1988 तक चली और यह संगठन भी कोई प्रभावी भूमिका नहीं निभा सका।

इसके बाद इस्लामिक सैन्य और आतंकवाद विरोधी संगठन बनाया गया। मुख्य रूप से यह ईरान के खिलाफ था। सऊदी अरब इसका नेता था। अब तक तो यह कोई खास भूमिका नहीं निभा पाया है। अलबत्ता सदस्य देशों की संख्या 40 के आसपास पहुंच गई। यहां तक कि पाकिस्तान ने इस फोरम में कश्मीर का मसला अनेक बार उठाया,मगर उसे सफलता नहीं मिली।

इसके बाद इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) का जिक्र। यह संगठन तनिक ताकतवर है और संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर माना जाता है। लेकिन इसका आधार मजहबी है। इसका गठन 1969 में हुआ था। तीन साल बाद 1972 में इस संगठन ने अपना चार्टर अपनाया। पाकिस्तान इसका शुरुआती सदस्य था और बांग्लादेश बनने के बाद वह भी इसका सदस्य बन गया।

उसके बाद बांग्लादेश ने कई बार भारत को इसमें शामिल करने के लिए अनुरोध किया। उसका तर्क था कि जिस देश में विश्व की सारी मुस्लिम आबादी का दस प्रतिशत रहता हो, उसे संगठन से बाहर रखने का औचित्य नहीं है। तब तो बांग्लादेश भारत के मित्र देशों की सूची में था। हालांकि अब उसके सुर बदले हुए हैं।

बता दूं कि 1970 में भारत को विशेष आमंत्रित के तौर पर इसके शिखर सम्मेलन में बुलाया गया था, पर पाकिस्तान ने इतना उग्र विरोध किया कि वह बैठक में भाग नहीं ले सका। इसके बाद बांग्लादेश ने 2018 में भारत को पर्यवेक्षक के तौर पर आमंत्रित करने की बात कही, पर पाकिस्तान का अड़ियल रवैया बाधा बन गया। फिर भी 2019 में भारत को पाकिस्तान की खिलाफत के बावजूद शिखर सम्मेलन में न्यौता गया।

इस संगठन ने कश्मीर के मसले पर अनेक बार अनावश्यक दखल दिया। हर बार भारत ने उसे खारिज कर दिया। यह संगठन भी अभी तक अपने महत्व को स्पष्ट नहीं कर पाया है क्योंकि इसके सदस्य देश भी आपस में ही लड़ते रहे हैं। अनेक सदस्य देश तो भारत से साफ कहते हैं कि कश्मीर संबंधी संगठन के बयानों पर ध्यान नहीं दे।

असल बात तो यह है कि संगठन के अधिकतर मुस्लिम देशों के साथ भारत के सीधे कारोबारी रिश्ते हैं और वे भारत से यह संबंध चाहकर भी नहीं तोड़ सकते। लब्बोलुआब यह कि मजहबी धुरी पर टिके संगठन दरअसल बेअसर साबित हुए हैं। फिर इस समय अचानक एमडीए का गठन क्यों हुआ?

आते हैं तुर्की पर। तुर्की मक्का संगठन का महत्वपूर्ण सदस्य है। वह नाटो का सदस्य भी है और नाटो से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इन दिनों बहुत खफा हैं। रूस-यूक्रेन जंग में और फिर ईरान-इजराइल-अमेरिका जंग में नाटो देशों ने अमेरिका की पूंछ नहीं पकड़ी और ट्रम्प को आईना दिखा दिया। नाटो देश तो यूक्रेन-रूस जंग से बाहर आना चाहते हैं, पर उन्हें ठोस बहाना नहीं मिल रहा है। नाटो के अनेक सदस्य देश खुल्लमखुल्ला अमेरिका का विरोध कर चुके हैं। ऐसे में ट्रम्प जानते हैं कि तुर्की की सेना नाटो सेनाओं की तुलना में बड़ी और ताकतवर है। तुर्की कश्मीर के मामले में हमेशा पाकिस्तान के साथ रहा है और अमेरिका उस पर हमेशा भरोसा करता रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प भारत से चिढ़े हुए हैं। यह तथ्य छिपा नहीं है।

भारत के विरोध में अमेरिका हरदम पाकिस्तान के कंधे पर हाथ रखता रहा है। ऐसे में ट्रम्प ने नवोदित संगठन के बहाने एक तीर से तीन निशाने साधे हैं- इजराइल से दूरी, नाटो देशों को संदेश और भारत विरोधी मोर्चा बनाना ही एमडीए का असल उद्देश्य है। सऊदी अरब हमेशा से सुन्नीवाद के चलते पाकिस्तान के साथ रहा है और ईरान का धुर विरोधी है। वह अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर है। उसकी अपनी सेना कमजोर है। हां, वह पैसा खर्च कर सकता है। ईरान पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका को इसमें सऊदी अरब को शामिल करना जरूरी था। रही पाकिस्तान की बात तो वह असुरक्षित और भारत से आतंकित मुल्क है।

तेजी से बदल रही है भारत की तस्वीर

प्रह्लाद सबनानी

भारत के सबसे बड़े औद्योगिक घरानों, टाटा, बिरला, रिलायंस, अडानी, आदि को अपना व्यवसायिक साम्राज्य खड़ा करने में दशकों लग गए थे। इन समूहों को अपनी सम्पत्ति को 100 करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर तक पहुंचाने में लगभग 30 वर्षों का समय लगा था परंतु आज के युवावर्ग द्वारा स्थापित की जा रही कम्पनियों को अपनी सम्पत्ति को 100 करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंचाने में केवल 1 से 3 वर्ष का समय लग रहा है। भारत में समय बहुत तेजी से बदल रहा है और भारतीय युवा आज भारत की तस्वीर बदलने को उतावाले होते दिखाई दे रहे हैं। जून 2026 में एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स) का व्यवसाय करने वाली सर्वम कम्पनी ने अपनी स्थापना के केवल 3 वर्ष के अंदर ही 150 करोड़ (1.5 बिलियन) अमेरिकी डॉलर की सम्पत्ति खड़ी कर ली है। इसी प्रकार, आज जेप्टो एवं मेन्सा नामक ब्राण्ड कुछ ही महीनों में व्यवसाय के उस स्तर को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे हासिल करने में पुरानी बड़ी कम्पनियों को कई दशक लग गए थे। आज के समय में टेक्नॉलोजी के क्षेत्र में स्थापित हो रही कम्पनियों की तुलना यदि इसी क्षेत्र में लगभग 20/25 वर्ष पूर्व स्थापित कम्पनियों से भी की जाय तो सम्पत्ति खड़ी करने के समय में बहुत अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। वर्ष 2000 में स्थापित कम्पनियों को यूनिकोन (100 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सम्पत्ति बनाना) बनने में लगभग 20 वर्ष से अधिक का समय लग रहा था, वहीं वर्ष 2020 में स्थापित कम्पनियों को यूनिकोन बनने में केवल एक वर्ष का समय लग रहा है। वित्तीय क्षेत्र में स्थापित की गई कम्पनियों को यूनिकोन बनने में 30 वर्ष का समय लगा है। वहीं मेन्सा ब्राण्ड जैसी कम्पनी को यूनिकोन बनने में केवल 6 माह का समय लगा है। बाजार वही है, परंतु समय तेजी से बदल रहा है। इस परिवर्तन में भारतीय युवाओं की प्रमुख भूमिका रही है। आज भारत में व्यावसायिक घराने/खानदान एवं अमीर लोग कहीं पीछे छूट गए हैं एवं युवा पीढ़ी तेजी से

बिलिनायर की सूची में अपनी जगह बना रही है।

पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत में एक लाख से अधिक नए स्टार्ट-अप स्थापित हुए हैं। आज भारत ने अपने आप को, अमेरिका एवं चीन के बाद, दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्ट-अप इको सिस्टम में स्थापित कर लिया है। भारत में आज अधिक से अधिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से उपभोक्ता उत्पादों को बढ़ावा देने वाले स्टार्ट अप बन रहे हैं। किराना उत्पादों से संबंधित ऐप अधिक संख्या में बनाए जा रहे हैं क्योंकि यूपीआई जैसा पेमेंट गेटवे पूर्व से ही उपलब्ध है और भुगतान प्रणाली को अलग से विकसित करने की आवश्यकता ही नहीं है। साथ ही, 140 करोड़ नागरिकों का बायोमेट्रिक डाटा पहिले से ही सत्यापित है और यह उपभोक्ता उत्पादों से सम्बंधित ऐप बनाने वाले इंजीनियरों को उपलब्ध भी है। भारत में डिजिटल लाकर में 750 करोड़ से अधिक दस्तावेज जमा हो चुके हैं। सस्ता इंटरनेट डाटा उपलब्ध है एवं 90 करोड़ से अधिक भारतीय इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। इन परिस्थितियों के बीच आज 20 वर्ष के युवा एंटरप्रेन्योर को व्यवसाय स्थापना के प्रथम दिवस से ही पूरा भारत उसके उत्पाद के बाजार के रूप में उपलब्ध है। उक्त कारकों के चलते ही वर्ष 2021 में भारत में 45 नए यूनिकोन विकसित हुए थे।

भारत के पास आज दुनिया के सबसे स्मार्ट एवं कुशल इंजीनीयर तो हैं परंतु हमारे पास अपने गूगल, अपना यू ट्यूब एवं अपना फेस बुक नहीं है। क्योंकि, भारत में उच्च स्तर का तकनीकी नवाचार नहीं हो पा रहा है जिससे उच्च तकनीकी के ऐप भारत में कम बन रहे हैं। हालांकि, विकसित देशों में जो भी उच्च स्तर के तकनीकी नवाचार हो रहे हैं इनमें भारतीय इंजिनीयरों की भी महती भूमिका रहती है। इसी कारण से भारतीय इंजीनियरों की विकसित देशों में भारी मांग है। भारतीय युवाओं को दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन करने के स्थान पर भारत में उच्च तकनीकी के नवाचार करने की ओर पूरा ध्यान देना चाहिए। अब तो विकसित देश भी यह मानने लगे हैं कि वर्तमान सदी केवल भारत की है। कई विकसित देशों सहित चीन में जनसंख्या वृद्धि दर अब ऋणात्मक हो चुकी है। साथ ही, इन देशों में वृद्ध नागरिकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पूरे विश्व में आज भारत एक युवा देश के रूप में उभर रहा है। अत: भारतीय युवाओं से न केवल भारत में आर्थिक विकास को गति देने बल्कि विश्व के अन्य कई देशों में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देने की अपेक्षा की जा रही है। कई देशों ने तो अपनी संसद में प्रस्ताव पास करने के उपरांत भारत सरकार से भारतीय युवाओं को इन देशों में भेजने की मांग की है।

भारतीय युवा आज न केवल भारत में तेजी से यूनिकोन विकसित कर रहा है बल्कि आज भारतीय अन्य देशों में पहुंच कर अपने व्यापार का विस्तार भी कर रहे हैं, इसी कारण से आज प्रतिवर्ष भारत से लगभग 7 लाख नागरिक विभिन्न देशों में जाकर बस रहे हैं। श्री लक्ष्मी मित्तल ने ब्रिटेन में आरसेलोर स्टील कम्पनी खरीद ली है। यह कम्पनी पूर्व में बीमार कम्पनी की श्रेणी में शामिल थी परंतु मित्तल समूह ने इसे आज विश्व की सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कम्पनी बना दिया है। इसी प्रकार वर्ष 2008 में टाटा समूह ने जैग्वार एवं लैंड रोवर कम्पनी को खरीद लिया था। भारतीय मूल के नागरिक आज ब्रिटेन में जायदाद निवेशकों के क्षेत्र में सबसे बड़े निवेशक माने जा रहे है। यूरोप में आज भारतीय कम्पनियां सबसे अधिक राशि का निवेश करती हुई दिखाई दे रही हैं और यूरोपीयन कम्पनियों का अधिग्रहण कर रही है। अमेरिका में भी लगभग यही स्थिति है। अमेरिका में सबसे बड़ी एल्यूमिनियम उत्पादक कम्पनी को भारतीय ने खरीद लिया है।

राहुल का नया हथियार बनता 'चिट्ठी बम'

हरीश गुप्ता

विपक्ष के नेता राहुल गांधी को शायद अपने राजनीतिक तरकश में एक नया हथियार मिल गया है - चिट्ठी। वे अपने पद का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के मुख्यमंत्रियों को सीधे पत्र लिखने में कर रहे हैं, विवादित मुद्दों को सार्वजनिक कर रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर हल्द्वानी के रामलीला मैदान के शुद्धिकरण में शामिल लोगों के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। यह शुद्धिकरण कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (जो दलित वर्ग से हैं) द्वारा वहां आयोजित एक जनसभा के बाद किया गया था। हालांकि, राहुल गांधी के समर्थक इस मुद्दे पर जीत की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन मामला दिन-ब-दिन और भी पेचीदा होता जा रहा है। दूसरा विकल्प यह हो सकता है कि वे किसी महत्वपूर्ण स्थान पर धरना दें और सरकार पर दबाव बनाएं, जैसा पैलेट गन मामले में हुआ था। 25 अगस्त को राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने संयुक्त रूप से मोदी को पत्र लिखकर आगामी जाति जनगणना के लिए प्रस्तावित खुली प्रश्नावली को रद्द करने की मांग की। इससे एक दिन पहले, राहुल ने विरोध प्रदर्शन कर रहे आदिवासी छात्रों की शिकायतों को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा था। ऐसा लगता है कि उस पत्र का काफी असर हुआ है। राहुल चाहते थे कि आदिवासी छात्राओं के लिए छात्रावास में दाखिले की 30 साल की आयु सीमा को हटाया जाए। महाराष्ट्र सरकार ने आदिवासी छात्रावासों में प्रवेश के लिए 30 वर्ष की आयु सीमा समाप्त कर दी। राहुल का हालिया पत्र-अभियान उनके सहयोगी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखे पत्र से शुरू हुआ था, जो छात्र आंदोलन से जुड़ा था। राहुल के लिए यदि संसद एक युद्धक्षेत्र है, तो लेटरहेड दूसरा युद्धक्षेत्र बन रहा है।

राज्यपालों के फेरबदल की तैयारी- सत्ताधारी भाजपा में हुए फेरबदल के बाद लोक भवनों में भी फेरबदल की संभावना है। मार्च में राज्यपालों की नियुक्ति

और तबादलों का एक दौर हो चुका है, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि एक और फेरबदल की तैयारी शुरू हो गई है। करीब आधा दर्जन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए राज्यपाल और उपराज्यपाल नियुक्त किए जाने की उम्मीद है। कम से कम सात राज्यपाल और उपराज्यपाल अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और बदलाव की प्रतीक्षा में हैं। ऐसे में कुछ अनुभवी नेताओं के लिए राजभवन अगला संभावित ठिकाना हो सकता है। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक इस फेरबदल के प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जुलाई 2019 से पद पर हैं, जबकि गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भी लंबा कार्यकाल पूरा कर लिया है। भाजपा उत्तर प्रदेश के राजभवन के लिए किसी ब्राह्मण चेहरे पर विचार कर रही है - यह नियुक्ति राज्य में काफी राजनीतिक महत्व रख सकती है। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त), जो पूर्व उपसेना प्रमुख रह चुके हैं, पंजाब से अच्छी तरह परिचित हैं और वहां उनकी अच्छी पकड़ भी है। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। कर्नाटक में भी राज्यपाल बदलने की संभावना है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत की जगह किसी और को लाया जा सकता है, क्योंकि 2028 में विधानसभा चुनाव हैं और भाजपा एक अधिक राजनीतिक रूप से सक्रिय चेहरे को प्राथमिकता दे सकती है। मध्यप्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई सी। पटेल भी पांच साल पूरे कर चुके हैं। इसके अलावा, चार केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल पांच वर्ष पूरे कर चुके हैं, जिससे व्यापक फेरबदल की संभावना बढ़ गई है। तमिलनाडु भी इस प्रक्रिया में शामिल हो सकता है क्योंकि केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं।

छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र सीमा पर टाइगर की दस्तक से दहशत: बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ा

मोहला-मानपुर। महाराष्ट्र और बस्तर की सीमा से लगे औंधी क्षेत्र में एक बार फिर बाघ की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत है। पिछले करीब एक सप्ताह से गट्टेपायली, घोटियाकन्हार और गट्टेपायली इलाके में अलग-अलग समय पर ग्रामीणों ने बाघ को देखने की बात कही है। गट्टेपायली गांव के पास मुख्य सड़क किनारे बाघ के पगमार्क भी मिले हैं। इसके बाद वन विभाग ने इलाके में गश्त बढ़ाने के साथ संभावित विचरण क्षेत्र में ट्रैप कैमरे लगाए हैं। बता दें कि मौजुदा स्थिति को देखते हुए वन परिक्षेत्र अधिकारी प्रवीण देहारी के नेतृत्व में वन विभाग की टीम दिन और रात लगातार गश्त कर रही है। टीम गांवों में पहुंचकर ग्रामीणों के साथ बैठक कर उन्हें सावधानी बरतने की समझाइश भी दे रही है। बाघ की मौजूदगी का असर ग्रामीणों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। खेती-किसानी के इस मौसम में किसान डर के बीच खेतों में जा रहे हैं। वहीं स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी अभिभावक चिंतित हैं। बाघ के डर से आसपास के गांवों से बागडोंगरी माध्यमिक शाला आने वाले कई बच्चे पिछले कुछ दिनों से स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं। बागडोंगरी माध्यमिक शाला पहुंचकर वन अमले ने शिक्षकों से बच्चों की सुरक्षा को लेकर चर्चा की। रेंजर ने शिक्षकों से कहा कि वे बच्चों के पालकों से चर्चा कर स्कूल आने-जाने के लिए सुरक्षित व्यवस्था बनाने का प्रयास करें। इसमें वन विभाग भी सहयोग करेगा। घोटियाकन्हार और गट्टेपायली में ग्रामीणों के साथ बैठक कर वन विभाग ने उन्हें बाघ से सुरक्षा के उपाय बताए। ग्रामीणों से अकेले आने-जाने से बचने और खेतों में संभव हो तो समूह में जाने की अपील की गई। बाघ दिखाई देने पर उसके पास नहीं जाने और तत्काल वन विभाग को सूचना देने कहा गया। रेंजर प्रवीण देहारी ने क्षेत्र में बाघ की मौजूदगी की पुष्टि करते हुए कहा कि बाघ अपने प्राकृतिक आवास जंगल में ही है। क्षेत्र जंगल से घिरा होने के कारण कभी-कभी बाघ ग्रामीण इलाकों की ओर आ सकता है। वन विभाग की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ स्थिति पर नजर रख रही है और हालात काफी हद तक नियंत्रण में हैं। उन्होंने बताया कि बाघ के संभावित विचरण वाले इलाकों में ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। इनके जरिए बाघ की लोकेशन और गतिविधियों पर नजर रखने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ग्रामीणों से वन विभाग का सहयोग करने और अतिरिक्त सतर्कता बरतने की अपील की है।औंधी और आसपास का इलाका पिछले करीब दो वर्षों से बाघ की आवाजाही से प्रभावित है। महाराष्ट्र सीमा के उस पार हाल ही में दोलेंदा गांव में बाघ ने एक ग्रामीण पर हमला कर उसकी जान ले ली थी।

गढ़चिरौली से बस्तर लौटे 50 पूर्व माओवादी

साथियों ने दी भावुक विदाई, वहीं पूर्व माओवादी जम्पन्ना ने उठाए सवाल

जगदलपुर। कभी घने जंगलों में ए-47 जैसे आधुनिक हथियारों के साथ घूमने वाले, कभी एक-दूसरे के लिए जान लेने और जान देने को तैयार रहने वाले माओवादी, आज जब एक-दूसरे से बिछड़े, तो आंखों से आंसू नहीं रुके। तस्वीर ऐसी थी जिसे देखकर शायद कोई भी ठिठक जाए जो लोग कभी बंदूक के साए में जिंदगी जीते थे, आज सामान्य जिंदगी की ओर लौटते हुए एक-दूसरे को गले लगाकर रोते नजर आए। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के पुनर्वास का सिलसिला अब अगले चरण में पहुंच गया है। पिछले साल पूर्व माओवादी नेता वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति के नेतृत्व में बड़ी संख्या में माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया था। सुरक्षा कारणों से इन्हें गढ़चिरौली के पुलिस पुनर्वास केंद्र में रखा गया। यहां उनकी जिंदगी की दिशा बदलने की कोशिश की गई किसी को स्किल ट्रेनिंग दी गई, कई पूर्व माओवादियों के रिवर्स नसबंदी ऑपरेशन कराए गए और कुछ माओवादी जोड़ों ने नई जिंदगी की शुरुआत शादी के साथ की। अब उसी पुनर्वास प्रक्रिया के तहत इन्हें धीरे-धीरे उनके मूल गांव और जिलों में वापस भेजा जा रहा है। पहले चरण में 50 पूर्व माओवादियों को गढ़चिरौली से बस्तर के अलग-अलग जिलों में उनके गृहग्राम के लिए रवाना किया गया। लेकिन विदाई के वक्त जो तस्वीर सामने आई, उसने पूरी कहानी का दूसरा चेहरा दिखा दिया। कभी जंगलों में हथियारों के साथ साथ चलने वाले ये लोग, अब एक-दूसरे से बिछड़ने के दर्द में गले मिलकर रो रहे थे। हालांकि, इस पूरी प्रक्रिया पर पूर्व माओवादी नेता जिनुगु नरसिम्हा रेड्डी उर्फ जम्पन्ना ने सवाल भी खड़े किए हैं। प्रेस नोट जारी कर जम्पन्ना ने कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को लंबे समय तक पुनर्वास केंद्र में पुलिस निगरानी में रखने के बजाय, आत्मसमर्पण के बाद जल्द से जल्द उनके घर भेजा जाना चाहिए, ताकि वे सामान्य जिंदगी में वापस लौट सकें। कुल मिलाकर जंगल से शुरू हुआ सफर अब गांव की ओर लौट रहा है फर्क सिर्फ इतना है कि कभी इन हाथों में हथियार हुआ करते थे, लेकिन आज वही हाथ विदाई के वक्त एक-दूसरे को कसकर पकड़कर यह कह रहे थे, अब जिंदगी की लड़ाई बंदूक से नहीं, सामान्य जिंदगी जीकर लड़नी है।

स्कूल निरीक्षण में पहुंचे नपा अध्यक्ष ने बच्चों संग किया मध्यान्ह भोजन

मुंगेली। मुंगेली नगर पालिका स्थित जिस शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में नगर पालिका अध्यक्ष रोहित शुक्ला ने पढ़ाई की थी, आज उसी स्कूल में वे पालिका अध्यक्ष की जिम्मेदारी के साथ पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान मध्यान्ह भोजन के समय उन्होंने विद्यार्थियों के साथ मध्यान्ह भोजन किया। पुराने स्कूल में लौटने और बच्चों के साथ भोजन करने का यह पल उन्हें उनके विद्यार्थी जीवन की यादों में ले गया।

रोहित शुक्ला ने कहा कि आज वे जिला शिक्षा अधिकारी के साथ इसी स्कूल का निरीक्षण करने आए हैं। संयोग से निरीक्षण के दौरान भोजन का समय हो गया, इसलिए विद्यार्थियों के साथ बैठकर मध्यान्ह भोजन किया। उन्होंने कहा कि इसी स्कूल में उन्होंने भी पढ़ाई की है, इसलिए यहां आना उनके लिए केवल निरीक्षण नहीं, बल्कि पुरानी यादों से जुड़ा अनुभव भी है।

निरीक्षण के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी एलपी डाहिरे के साथ विद्यालय के प्राचार्य विजय सोनी, संकुल समन्वयक सुशील जांगड़े एवं अन्य शिक्षकगण उपस्थित रहे। विद्यालय की विभिन्न आवश्यकताओं को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान भौतिकी एवं हिंदी विषय के व्याख्याताओं की आवश्यकता के साथ ही सहायक ग्रेड-3 एवं प्यून के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई।

निरीक्षण के दौरान यह भी सामने आया कि विद्यालय में कक्षा 6 से 12 तक कक्षाओं की संख्या अधिक है, जबकि उपलब्ध अध्यापन कक्षों की संख्या कम है। विद्यार्थियों की इस समस्या के समाधान के लिए नगर पालिका अध्यक्ष एवं नगर पालिका अभियंता ने अतिरिक्त भवन निर्माण के लिए स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान शीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ कराए जाने की बात कही गई।

जिला शिक्षा अधिकारी एलपी डाहिरे ने कक्षा 6 के विद्यार्थियों से 25 तक के पहाड़े पूछे। इसके साथ ही हिंदी एवं अंग्रेजी पठन का भी परीक्षण लिया। उन्होंने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए उनकी पढ़ाई और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान मध्यान्ह भोजन के समय नगर पालिका अध्यक्ष रोहित शुक्ला एवं जिला शिक्षा अधिकारी एलपी डाहिरे ने विद्यार्थियों के साथ बैठकर मध्यान्ह भोजन करने से पहले भोजन मंत्र के पश्चात विद्यार्थियों को चावल, दाल, चना-आलू की सब्जी एवं अचार-पापड़ का वितरण किया गया। भोजन की गुणवत्ता संतोषजनक पाए जाने पर चखना पंजी में भी प्रविष्टि दर्ज की गई। एक तरफ स्कूल की व्यवस्थाओं और विद्यार्थियों की पढ़ाई से जुड़ी जरूरतों का निरीक्षण चल रहा था, तो दूसरी तरफ इसी स्कूल में कभी विद्यार्थी रहे नगर पालिका अध्यक्ष का बच्चों के साथ बैठकर मध्यान्ह भोजन करना पूरे निरीक्षण का भावनात्मक पल बन गया।

बीच सड़क पर पुलिस जवानों ने सिर पर पिस्टल तानकर हिस्ट्री शीटर दबोचा

जगदलपुर। बस्तर के जगदलपुर स्थित नए बस स्टैंड में गुरुवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब ओडिशा पुलिस ने सिविल ड्रेस में पहुंचकर एक हिस्ट्रीशीटर को घेर लिया। शराब दुकान के पास हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी को चारों तरफ से घेरकर पिस्टल की नोक पर दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान टुन्ना महाजन के रूप में बताई जा रही है, जो ओडिशा से फरार होकर बस्तर पहुंचा था।

जानकारी के मुताबिक, ओडिशा पुलिस को टुन्ना महाजन के जगदलपुर में होने की सूचना मिली थी। इसके बाद सिविल ड्रेस में पहुंची पुलिस टीम ने नए बस स्टैंड के पास शराब दुकान के करीब उसे घेर लिया। पुलिसकर्मियों ने आरोपी को चारों तरफ से घेरकर काबू में किया और मौके से अपने साथ ले गई। इस पूरी कार्रवाई का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में पुलिसकर्मी आरोपी को पकड़कर ले जाते दिखाई दे रहे हैं। वहीं, उसके सिर के पास पिस्टना तना हुआ नजर आ रहा है। कार्रवाई के दौरान

कहा: ज्यादा हुआ तो गोली मार देंगे

एक पुलिसकर्मी की आवाज भी वीडियो में सुनाई देती है- ज्यादा हुआ तो गोली मार देंगे। पुलिस की इस कार्रवाई को देखकर मौके पर मौजूद लोग भी हैरान रह गए।ओडिशा पुलिस के मुताबिक, टुन्ना महाजन के खिलाफ चोरी और डकैती के कई मामले दर्ज हैं। उस पर बोरिगुमा पुलिस पर पांच राउंड फायरिंग करने का भी आरोप है। इसी मामले में पुलिस उसकी तलाश कर रही थी और उसके बस्तर पहुंचने की जानकारी मिलने के बाद टीम ने जगदलपुर में कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार, टुन्ना महाजन के तार बस्तर में हुई चोरी की कुछ वारदातों से भी जुड़े होने की जानकारी सामने आई है। इनमें गिरोला मंदिर समेत अन्य मंदिरों में हुई चोरी की घटनाएं शामिल हैं। अब ओडिशा पुलिस इन वारदातों में उसकी कथित भूमिका की भी जांच कर रही है। ओडिशा पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी के कब्जे से एक कंट्री मेड पिस्टल और चोरी का सोना बरामद किया गया है। बरामद सामान को लेकर भी पुलिस जांच कर रही है। ओडिशा से फरार होकर बस्तर पहुंचे टुन्ना महाजन को पुलिस ने नए बस स्टैंड में ही दबोच लिया।

एसीबी ने प्राचार्य व लिपिक को 10 हजार रूपये रिश्वत लेते पकड़ा

जांजगीर-चांपा। जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक प्राचार्य और एक लिपिक को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार, अंजुलता सोनी (प्राचार्य) और विकास मसीह (लिपिक) को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबीकी टीम ने पकड़ा है।

पूरा मामला शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय किरारी का है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपियों ने अपने ही स्कूल के बाबू मनीष राठौर से वेतन वृद्धि का एरियर 80 हजार रुपए निकालने के एवज में पैसों की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद एसीबीने जाल बिछाकर कार्रवाई की और रिश्वत की रकम लेते समय दोनों को धर दबोचा।

इस कार्रवाई मे एसीबी के 13 अधिकारियों की विशेष टीम शामिल रही। टीम आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले से जुड़े दस्तावेजों की जांच भी जारी है। एसीबीकी इस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। बता दें कि एसीबी बिलासपुर की यह लगातार 56वीं ट्रैप कार्रवाई है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

महानदी में जलस्तर बढ़ने से आसपास बसे गांवों में अलर्ट

धमतरी। जिले में लगातार बारिश के चलते जलाशयों का जलस्तर बढ़ने के बाद महानदी के आसपास बसे गांवों को अलर्ट किया गया है. गंगरेल जलाशय करीब 97 प्रतिशत भर चुका है, जिसके चलते इसके तीन गेट खोलकर कुल 4670 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसके बाद से प्रशासन ने नदी के आसपास के गांवों में विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। जानकारी के अनुसार 3 सितंबर की सुबह 8 बजे की स्थिति के अनुसार गंगरेल जलाशय 97.40 प्रतिशत, मुरूमसिल्ली 98.61 प्रतिशत, दुधावा 86.86 प्रतिशत और सोंढूर जलाशय 69 ।25 प्रतिशत भर चुका है। लगातार हो रही पानी की आवक को देखते हुए जलाशयों और नदी-नालों के जलस्तर पर प्रशासन की निगरानी बढ़ा दी गई है। इसमें 1410 क्यूसेक पानी रुद्री बैराज के माध्यम से महानदी मुख्य नहर में भेजा जा रहा है, जबकि 3360 क्यूसेक पानी सीधे महानदी में प्रवाहित किया जा रहा है। प्रशासन का मानना है कि बारिश और जलाशयों में पानी की आवक इसी तरह बनी रही तो आने वाले समय में महानदी का जलस्तर और बढ़ सकता है।

एक्शन व प्रोग्रेस रिपोर्ट पर होगी ऑनलाइन वन विभाग की मॉनिटरिंग

जगदलपुर। बस्तर के जंगलों में अवैध कटाई, शिकार और वन्यजीव अपराध समेत उन पर होने वाली कार्रवाई को पारदर्शी बनाया जाएगा। इसके लिए पीओआर एप्लीकेशन को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई।जगदलपुर वन विद्यालय में वृत्तस्तरीय कार्यशाला में संभागीय वनमंडल अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। सीसीएफ बस्तर स्टायलो मंडावी ने बताया कि जगदलपुर शहर के वन विद्यालय में वनवृत ऑनलाइन पीओआर एप्लिकेशन के लिए कार्यशाला आयोजित हुई थी। इसमें वन मंडल बस्तर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा के साथ ही वाइल्ड लाइफ कांगेर वैल्ली नेशनल पार्क और इंद्रावती टाइगर रिजर्व के सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यशाला में वन अपराध दर्ज करने से लेकर उसकी जांच और आगे की कार्रवाई तक की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने की ट्रेनिंग दी गई। सीसीएफ स्टायलो मंडावी ने कहा कि जंगलों में शिकार और वन्यजीव अपराधों के मामलों में भी हम वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत जांच करते हैं।

रामानुजगंज फोरेस्ट रेंज में 9 हाथियों का उत्पात, अलर्ट

बलरामपुर। रामानुजगंज फोरेस्ट रेंज में हाथियों के दल का उत्पात लगातार जारी है। नौ हाथियों का दल यहां विचरण कर रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, वन विभाग की टीम हाथी विचरण प्रभावित क्षेत्रों में लगातार गश्त और मुनादी कर ग्रामीणों को सतर्क कर रही है। रामानुजगंज वन परिक्षेत्र में हाथियों के दल के उत्पात से कई गांव में रहने वाले ग्रामीण डर और दहशत के माहौल में रह रहे हैं। हाथी खेतों में लगी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कनकपुर के अल्मा गोदाम पारा में रहने वाले ग्रामीणों को हाथियों से संभावित खतरे को देखते हुए शासकीय स्कूल में शिफ्ट किया गया है। नौ हाथियों का दल झारखंड से कन्हर नदी के रास्ते रामानुजगंज फोरेस्ट रेंज में पहुंचा है। बीते दस बारह दिनों से रामानुजगंज में घूम रहे हैं। दिन के समय हाथियों का दल जंगल में रहता है लेकिन शाम ढलते ही हाथी गांव की बस्तियों में पहुंचकर उत्पात मचाते हैं। हाथी प्रभावित क्षेत्र में वन विभाग द्वारा हाथियों की गतिविधि पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।

बैडमिंटन लीग के लिए 77 खिलाड़ियों की नीलामी पूरी

नारायणपुर। दुर्गम अबूझमाड़ क्षेत्र को खेल गतिविधियों से जोड़ने की दिशा में नारायणपुर पुलिस की पहल लगातार आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में आयोजित होने वाली अबूझमाड़ बैडमिंटन लीग (एबीएल) सीजन-3 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। कुल 110 पंजीकृत खिलाड़ियों में से 77 खिलाड़ियों का चयन करते हुए उन्हें कुल 6 फ्रेंचाइजी टीमों में शामिल किया गया है। लीग के मुख्य मुकाबले 10 से 12 सितंबर तक नारायणपुर स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम में खेले जाएंगे। प्रतियोगिता की खास बात यह है कि इसमें स्थानीय खिलाड़ियों के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे। अबूझमाड़ बैडमिंटन लीग सीजन-3 के प्रथम चरण के तहत 1 सितंबर को नारायणपुर के डीआरजी ट्रेनिंग एरेना में खिलाड़ियों की ऑक्शन प्रक्रिया आयोजित की गई। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक संदीप पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अक्षय साबद्रा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऐश्वर्य चंद्राकर भी मौजूद रहे।

पोटा केबिन आवासीय विद्यालय का शिक्षा मंत्री ने किया निरीक्षण

बीजापुर। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने बुधवार को बीजापुर जिले के प्रवास के दौरान पुसनार स्थित पोटा केबिन आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय में बच्चों को दी जा रही शिक्षा, भोजन, शयनकक्ष, भोजनकक्ष और स्वच्छता व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बच्चों से आत्मीयता के साथ गोंडी भाषा में संवाद करते हुए उनकी पढ़ाई और दैनिक दिनचर्या की जानकारी ली। इस दौरान मंत्री ने कहा कि आवासीय विद्यालयों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के साथ उनके संस्कार, अनुशासन और व्यक्तित्व विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने विद्यालयों में नियमित प्रार्थना, प्रेरणा गीत, योग, खेलकूद, संगीत और महापुरुषों की जीवनी जैसी रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। जिला कार्यालय में आयोजित शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में मंत्री गजेन्द्र यादव ने जिले की शैक्षणिक व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।

बमलाई, बम्लेश्वरी या बगलामुखी? डोंगरगढ़ की देवी के नाम पर फिर गरमाया विवाद

डोंगरगढ़। डोंगरगढ़ वाली मां बम्लेश्वरी के नाम और इतिहास को लेकर शुरू हुई नई बहस ने डोंगरगढ़ की पुरानी धार्मिक मान्यताओं और ऐतिहासिक दस्तावेजों को फिर सामने ला दिया है। विवाद की शुरुआत कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के नाम से सामने आए उस कथित कथन से हुई, जिसमें देवी के नाम को भगवान शिव के डमरू से निकली 'बम' ध्वनि से जोड़ा गया।

गोंड समाज ने इसे अपनी परंपरा के विपरीत बताते हुए राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर खंडन, स्पष्टीकरण और माफी की मांग की है। गोंड समाज की मान्यता है कि डोंगरगढ़ की देवी को पुरानी परंपरा में 'दाई बमलाई' कहा जाता था, और बाद में 'बम्लेश्वरी' नाम प्रचलित हुआ।

समाज इससे जुड़े धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भों का उल्लेख करता है और डॉ. मोतीरावण कंगाली की पुस्तक 'डोंगरगढ़ की बमलाई दाई बमलेश्वरी' को भी इसका महत्वपूर्ण आधार मानता है। गोंड समाज के अनुसार यह केवल देवी के नाम का सवाल नहीं, बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान और पुरानी परंपरा से जुड़ा विषय है। हालांकि, इन दावों की ऐतिहासिक पुष्टि के लिए प्राथमिक दस्तावेजों की जरूरत होगी।

दूसरी तरफ करीब डेढ़ सौ साल पुराने ब्रिटिशकालीन रिकॉर्ड में एक अलग नाम सामने आता है। अलेक्जेंडर कनिंघम की रिपोर्ट में 1864 के डोंगरगढ़ का उल्लेख करते हुए बगलामुखी देवी के सम्मान में रविवार को लगने वाले साप्ताहिक बाजार की जानकारी दर्ज है। यानी उस दौर के उपलब्ध लिखित रिकॉर्ड में देवी का संदर्भ बगलामुखी नाम से मिलता है। यह रिकॉर्ड महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन इससे यह अपने आप साबित नहीं होता कि बगलामुखी से बमलाई और फिर बम्लेश्वरी नाम कैसे बना।

वर्तमान में मंदिर की आधिकारिक पहचान मां बम्लेश्वरी के रूप में है। मंदिर की वेबसाइट भी पहाड़ी स्थित मंदिर को मां बम्लेश्वरी और नीचे स्थित मंदिर को छोटी बम्लेश्वरी के रूप में दर्ज करती है। ऐसे में सामने तीन अलग-अलग संदर्भ हैं, ऐतिहासिक रिकॉर्ड में बगलामुखी, गोंड समाज की परंपरा में दाई बमलाई और वर्तमान धार्मिक व्यवस्था में बम्लेश्वरी। इन नामों को एक-दूसरे से जोड़ने वाले प्रमाणित दस्तावेज सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं हैं। यही इस पूरे विवाद का सबसे अहम सवाल है।

आखिर सच क्या है? क्या बगलामुखी, बमलाई और बम्लेश्वरी एक ही देवी के अलग-अलग समय में प्रचलित नाम हैं, या इनके पीछे अलग परंपराओं की कहानी है? इसका जवाब किसी एक कथा या दावे से नहीं, बल्कि पुराने राजकीय दस्तावेजों, मंदिर के अभिलेखों, पुरातात्विक प्रमाणों और गोंड समाज की मौखिक परंपराओं को एक साथ रखकर तलाशना होगा।

ट्रेलर चालक ने चोरों की स्कॉर्पियो को ठोका

कटघोरा। कोरबा जिले में कटघोरा बाईपास पर डीजल चोर गिरोह के आतंक से ट्रक चालक और मालिक परेशान हैं। गुरुवार तड़के स्कॉर्पियो सवार 6 से 7 चोरों ने ट्रेलरों से डीजल चोरी करने की कोशिश की। इसी दौरान एक ट्रेलर चालक की नजर चोरों पर पड़ गई। चालक ने हिम्मत दिखाते हुए ट्रेलर स्टार्ट कर स्कॉर्पियो को जोरदार टक्कर मार दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पूरी वारदात पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बताया जा रहा है कि तड़के स्कॉर्पियो में सवार होकर पहुंचे 6 से 7 आरोपियों ने सड़क किनारे खड़े ट्रेलरों को निशाना बनाया और डीजल निकालने लगे। इसी दौरान एक ट्रेलर चालक की नजर आरोपियों पर पड़ गई। चालक को धमकाने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक ने हिम्मत दिखाते हुए अपना ट्रेलर स्टार्ट कर दिया और भाग रहे चोरों की स्कॉर्पियो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। चालक ने तत्काल डायल 112 को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की स्कॉर्पियो वाहन को जब्त कर लिया है। वाहन से डीजल के कंटेनर भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अब पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी में जुटी है। कटघोरा थाना प्रभारी प्रेमचंद साहू ने बताया कि वाहन जब्त कर लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि पाली थाना क्षेत्र में भी डीजल चोरी की ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इस घटना के बाद ट्रक चालक और मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है।

31 मार्च 2026 को छत्तीसगढ़ ने एक ऐतिहासिक अध्याय लिखा। दशकों तक विकास में सबसे बड़ी बाधा रहे नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक सफलता ने राज्य को नई दिशा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में लिया गया संकल्प आज ज़मीन पर साकार होता दिख रहा है। अब मई 2026 में पूरा छत्तीसगढ़ बदलाव की नई तस्वीर देख रहा है। वर्षों से उपेक्षित रहे बस्तर और दण्डकारण्य क्षेत्र तेज़ी से विकास, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और रोजगार के नए दौर में आगे बढ़ रहे हैं। राज्य की 3 करोड़ जनता की ओर से इस ऐतिहासिक परिवर्तन के लिए केंद्र सरकार का आभार।

— विष्णु देव साय,
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

बस्तर में लौटी शांति

चार दशकों के नक्सल दौर का अंत, विकास के नए युग की शुरुआत

लंबे समय तक नक्सलवाद की पहचान के साथ जिया बस्तर अब शांति और प्रगति की एक नई सुबह का साक्षी बन गया है। सुरक्षाबलों के कड़े संकल्प, सरकार की ठोस नीतियों और जनता के सहयोग से बस्तर के साथ ही पूरे देश से नक्सलवाद का अंत हो गया है। यह बंदूकों के शांत होने का समय नहीं, बल्कि असली बस्तर के उभरने का वक्त है।

सुरक्षा का मजबूत कवच

अबूझमाड जैसे दुर्गम इलाकों में सुरक्षा कैंप और ऑपरेशन से नक्सलियों के गढ़ ध्वस्त हुए। 2019 से अब तक 320 से ज्यादा नए कैंप स्थापित किए गए।

नक्सल मोर्चे पर कैसे मिली कामयाबी

छत्तीसगढ़ में लाल आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार ने बस्तर में करीब 24,000 कर्मियों की तैनाती की, जिसमें जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी), बस्तर फाइटर्स, स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) और सीआरपीएफ शामिल हैं. इन सभी ने पहले दुर्गम इलाकों में एफओबी यानी फार्वर्ड बेस कैंप स्थापित किया. साल 2019 और 2025 के बीच 320 से ज्यादा नए शिविर स्थापित किए गए, जिससे सुरक्षा बलों को उन नक्सली गढ़ों में सुरक्षा की कमी की भरपाई का अवसर मिला, जहां पहले जाना असंभव था, जिनमें अबूझमाड़ क्षेत्र भी शामिल है।

विकास की नई रोशनी

सड़कें, स्कूल, अस्पताल, राशन की दुकान, आधार और राशन कार्ड हर गांव तक पहुंच रहे हैं। जहां कभी बंदूकें थी, वहां अब विकास की किरणें बस्तर के अंतिम छोर तक चमक रही है।

ऑपरेशन से मिला निर्णायक सफलता

- ऑपरेशन प्रहार (2017), ऑपरेशन कगार (2024) और ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट (2025) जैसे बड़े अभियानों ने नक्सलियों के नेटवर्क और नेतृत्व को कमजोर किया।
- ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट (21 अप्रैल-11 मई 2025) में 24 प्लस नक्सली ढेर, 54 गिरफ्तार और 84 आत्मसमर्पण हुए।
- कुरांकुदा और अबूझमाड़ में संयुक्त ऑपरेशन में कई शीर्ष नक्सली मारे गए, जिसमें शीर्ष नेता केशव राव भी शामिल है।

जो जवान ठान लेते हैं, वो करके दिखाते हैं

जवानों के शौर्य का स्वर्णिम अध्याय

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों, कोबरा टीम, बीएसएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस और डीआरजी के साहस, बलिदान और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि 'जवान जो तय करते हैं, वो हासिल करते हैं।' शाह ने कहा कि सुरक्षा बलों ने माओवादियों के अड्डों को तहस-नहस कर विश्व को चौंका दिया है। उन्होंने बताया कि नक्सलवाद ने पिछले 35 वर्षों में हजारों लोगों की जान ली और आदिवासी क्षेत्रों को विकास से वंचित रखा। अब सरकार प्रभावित क्षेत्रों में अनाज, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, घर और शुद्ध पेयजल जैसी सुविधाएं पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि जब आदिवासी बच्चा बंदूक छोड़ पेंसिल पकड़ता है, तभी देश का भविष्य मजबूत होता है।

नक्सलियों की कमर तोड़ने वाले फैसले

- माओवादियों के वित्तीय नेटवर्क पर करारा प्रहार, संपत्तियों की जब्ती, संदिग्ध खनन व ठेकों पर रोक।
- नोटबंदी और डिजिटल भुगतान से नकदी की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई।
- एनआईए, ईडी और राज्य पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से शेल कंपनियों, एनजीओ और अर्बन नक्सलियों पर बड़ी कार्रवाई।

हर गांव में स्कूल | हर गांव में राशन की दुकान | हर तहसील में PHC, CHC | गैस के चूल्हे और आवास | रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के अवसर | जनजातीय संस्कृति और परंपराओं का सम्मान

हिड़मा के आतंक का अंत, बस्तर में लौट रहा शांति का वसंत

छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए माडवी हिड़मा को ढेर कर बस्तर में शांति और विकास की दिशा मजबूत की है। मुख्यमंत्री श्री साय ने इसे निर्णायक उपलब्धि बताते हुए कहा कि केंद्र-राज्य की संयुक्त रणनीति से बस्तर में विश्वास, सुरक्षा और विकास का नया दौर शुरू हुआ है।

पापाराव का आत्मसमर्पण बना साय सरकार की बड़ी सफलता

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय सरकार की प्रभावी रणनीति, पुनर्वास नीति और सुरक्षा अभियान के चलते बस्तर में नक्सलवाद तेजी से कमजोर हुआ है। पापाराव सहित 18 माओवादियों का आत्मसमर्पण शांति, विकास और जनविश्वास की बड़ी जीत है। अब बस्तर नक्सलमुक्त भविष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।

नक्सलवाद का अंत
विकास का आरंभ

संवाद-48873/2

सुरक्षित बस्तर – समृद्ध बस्तर – विकसित बस्तर

समरसता के संकल्प के साथ भाजपा ने किया कलश वंदन

भाजपा रायपुर ने किया कलश वंदन समरसता संकल्प अभियान समारोह

रायपुर। एकात्म परिसर जिला कार्यालय रायपुर में जिलाध्यक्ष ठाकुर ने बताया कि, भारतीय जनता पार्टी द्वारा संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती वर्ष को सामाजिक समरसता, समानता, भाईचारे एवं मानवता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के संकल्प के रूप में आज समरसता संकल्प अभियान के तहत कलश वंदन कार्यक्रम किया गया। जिसमें भाजपा के 20 मंडलों में यह कलश वितरण किया गया।

भाजपा द्वारा संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज समरसता संकल्प अभियान का देशव्यापी आयोजन किया जा रहा है। यह अभियान 29 जुलाई 2026 से 20 फरवरी 2027 तक चलेगा। अभियान का शुभारंभ संत रविदास जी की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर, वाराणसी से किया गया। भाजपा का प्रयास है कि संत रविदास जी के इन महान विचारों को केवल समारोहों तक सीमित न रखते हुए घर-घर और समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाया जाए। भाजपा ने 29 जुलाई 2026 से 20 फरवरी 2027 तक देशव्यापी संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज समरसता संकल्प अभियान चलाने की घोषणा की है। इसका मुख्य संदेश सामाजिक समरसता, समानता, भाईचारा और संत रविदास जी के विचारों को जन-जन तक पहुँचाना है।

संत रविदास जी को सिर्फ किसी एक समाज के संत नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के मार्गदर्शक के रूप में जाने जाते है उनके समता, समानता और सामाजिक समरसता के संदेश को समाज में फैलाना जाति और सामाजिक भेदभाव से ऊपर उठकर एकजुट और समरस समाज के निर्माण का संकल्प करना युवा पीढ़ी को संत रविदास जी के जीवन और विचारों से जोड़ना।

इस कार्यक्रम में रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा एवं रायपुर ग्रामीण के विधायक मोतीलाल साहू जी ने भी कार्यकर्ताओं को संत रवि दास जी के जीवन चरित्र के बारे में विस्तृत रूप से सभी को बताया ।

बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश मंत्री जयंती पटेल, निगम मंडल के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, अमरजीत छाबड़ा, प्रफुल्ल विश्वकर्मा, नन्दकुमार साहू, किशोर महानंद, अशोक पांडे, सीमा साहू, महामंत्री अमित मैशेरी, गुंजन प्रजापति, कार्यक्रम संयोजक सत्यम दूबा, नवीन शर्मा, अकबर अली, तुषार चोपड़ा, अर्चना हुकरे, श्रद्धा मिश्रा, रोहित द्विवेदी, पन्ना दुबे, पुष्पेंद्र उपाध्याय, अनीता देवांगन, कृतिका जैन, अखिलेश कश्यप, ओमप्रकाश साहू, अर्पित सूर्यवंशी, रजियंत ध्रुव, जीशान सिद्दीकी, सहित भाजपा के 20 मंडलों के अध्यक्ष, महामंत्री एवं बड़ी संख्या पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

प्रदेशभर में व्यापारियों और आयकर विभाग के बीच हुआ सीधा संवाद

रायपुर। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (ष्टढ्ढञ्ज) छत्तीसगढ़ एवं आयकर विभाग द्वारा आयोजित प्रदेश स्तरीय 'व्यापारी कर संवाद' कार्यक्रम गुरुवार को एक प्रदेश-एक दिन-एक संवाद की संकल्पना के साथ रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, अंबिकापुर, धमतरी एवं जगदलपुर सहित प्रमुख जिलों में एक साथ आयोजित हुआ। बड़ी संख्या में व्यापारियों एवं व्यापारिक संगठनों ने इसमें भाग लिया।

रायपुर स्थित कैट प्रदेश मुख्यालय में मुख्य आयकर आयुक्त संजीव मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने व्यापारियों से सीधे संवाद करते हुए कहा कि आयकर विभाग व्यापारियों के लिए मित्र एवं मार्गदर्शक की भूमिका में है। नोटिस मिलने पर घबराने के बजाय उसकी जानकारी को समझकर नियमानुसार समाधान की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में प्रमुख जिलों में संवाद हुआ है, जबकि अगले चरण में कैट एवं आयकर विभाग मिलकर प्रदेश के सभी 33 जिलों में व्यापारी संवाद आयोजित करेंगे।

कार्यक्रम में प्रमुख आयकर आयुक्त-1 मुनीश कुमार, अतिरिक्त आयकर आयुक्त श्री चिलाकला राजेश्वर रेड्डी एवं उप आयकर आयुक्त डॉ. गगन गिरी गोस्वामी सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। संवाद कार्यक्रम में व्यापारियों को आयकर प्रावधानों, प्रक्रियाओं एवं अनुपालन की जानकारी देने के साथ उनकी जिज्ञासाओं और व्यावहारिक समस्याओं का समाधान किया गया।

सीएआईटी के राष्ट्रीय वाइस चेयरमेन एवं राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य अमर पारवानी ने कहा कि 'व्यापारी कर संवाद' व्यापारियों और आयकर विभाग के बीच विश्वास, पारदर्शिता एवं सकारात्मक संवाद मजबूत करने की महत्वपूर्ण पहल है। इससे व्यापारियों को अधिकारियों के साथ सीधे संवाद का अवसर मिला है।सीएआईटी छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष परमानंद जैन ने कार्यक्रम की सफलता के लिए व्यापारियों एवं व्यापारिक संगठनों का आभार व्यक्त किया। रायपुर कार्यक्रम का संचालन प्रदेश महामंत्री श्री अवनीत सिंह ने किया तथा आभार सीए मुकेश मोटवानी ने माना।

इस अवसर पर कैट पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में व्यापारी उपस्थित रहे।

मंत्री राजवाड़े ने विकास कार्यों की समीक्षा की

रायपुर। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने आज सूरजपुर जिला के ओड़गी के जनपद पंचायत सभाकक्ष में आयोजित विकासखंड स्तरीय विभागीय समीक्षा बैठक में शामिल होकर क्षेत्र में संचालित विभिन्न योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने विभागवार योजनाओं और कार्यों की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने तथा शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समयबद्ध रूप से पहुंचाने के निर्देश दिए।

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने अधिकारियों को जमीनी स्तर पर योजनाओं एवं विकास कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने, निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा आमजन से जुड़ी समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और जनसुविधाओं के विस्तार के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे और विकास कार्यों का वास्तविक लाभ आमजन को मिले, इसके लिए अधिकारी पूरी जिम्मेदारी एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य करें।

समीक्षा बैठक में क्षेत्र में संचालित विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति, हितग्राहीमूलक योजनाओं के क्रियान्वयन तथा विभागीय योजनाओं की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को लंबित कार्यों में गति लाने और जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए।

संजय,अजय शुक्ला, शरद अवस्थी को मिला राज्यमंत्री का दर्जा

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने तीन प्रमुख नेताओं को राज्यमंत्री का दर्जा दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी किया। इस फैसले के तहत छत्तीसगढ़ राज्य योग आयोग के अध्यक्ष संजय अग्रवाल, छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के उपाध्यक्ष अजय शुक्ला और इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शरद अवस्थी को राज्यमंत्री की श्रेणी में शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार तीन अलग-अलग निकायों में कार्यरत पदाधिकारियों को यह महत्वपूर्ण दर्जा प्रदान किया गया है। योग आयोग के प्रमुख के रूप में संजय अग्रवाल का मुख्य दायित्व प्रदेश भर में योग का प्रचार-प्रसार करना तथा स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देना है। अजय शुक्ला को राज्य आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी के साथ राज्यमंत्री का दर्जा मिला है। यह बोर्ड विशेष रूप से वनांचल और आदिवासी क्षेत्रों में प्रचलित पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों तथा औषधीय पौधों से जुड़ी गतिविधियों के संवर्धन के लिए कार्य करता है। तीसरे नेता शरद अवस्थी इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं। इंद्रावती बेसिन के समग्र विकास तथा उससे जुड़े कार्यों के संचालन में इस प्राधिकरण की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है।

चेम्बर की रायपुर संभाग स्तरीय तिमाही समीक्षा

रायपुर। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष सतीश थौरानी के मार्गदर्शन एवं प्रदेश कोषाध्यक्ष निकेश बरड़िया की अध्यक्षता में चेम्बर भवन में रायपुर संभाग स्तरीय तिमाही समीक्षा एवं योजना बैठक आयोजित हुई। बैठक में संभाग की विभिन्न इकाइयों के पदाधिकारी शामिल हुए।निकेश बरड़िया ने कहा कि संभाग स्तरीय बैठक के माध्यम से अंतिम छोर के व्यापारियों की समस्याएं सीधे चेम्बर नेतृत्व तक पहुंचेंगी। उन्होंने बाजारों में सड़क, बिजली, पार्किंग, निकासी और अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रयास करने पर जोर दिया। बैठक में व्यापारियों ने ऑनलाइन बाजार की चुनौती, जीएसटी की तकनीकी समस्याएं, चिल्हर की कमी और ट्रेड लाइसेंस जैसे मुद्दे उठाए। 'वोकल फॉर लोकल' को बढ़ावा देने तथा जीएसटी कार्यशालाएं आयोजित करने पर भी सहमति बनी। विभिन्न इकाइयों ने अपनी गतिविधियों और आगामी तीन माह की कार्ययोजना प्रस्तुत की।कार्यक्रम का संचालन मनीष प्रजापति एवं आभार प्रदर्शन अमरदास खट्टर ने किया। बैठक में चेम्बर के पदाधिकारी एवं विभिन्न इकाइयों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

देवभोग ब्रांड गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीकः नेताम

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पशुधन विकास मंत्री रामविचार नेताम दुर्ग जिले के उरला (कुम्हारी) स्थित छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित (देवभोग) द्वारा आयोजित दुग्ध किसान सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देवभोग ब्रांड गुणवत्ता और अटूट विश्वास का प्रतीक बन चुका है, जिसने अपनी शुद्धता के बल पर देश में एक विशिष्ट पहचान कायम की है। कार्यक्रम के दौरान मंत्री श्री नेताम ने उरला दुग्ध संयंत्र में नवीन कैंटीन का उद्घाटन किया तथा दुग्ध संयंत्र की विभिन्न प्रणालियों का निरीक्षण कर कार्यप्रणाली का जायजा लिया। पशुपालकों के लिए तैयार विशेष मार्गदर्शिका का विमोचन पशुधन विकास मंत्री श्री नेताम ने पशुपालकों के लिए तैयार विशेष मार्गदर्शिका पुस्तिकाओं, देवभोग के रेडियो जिंगल, रिंगटोन एवं प्रेरक गीत का औपचारिक विमोचन किया। डेयरी क्षेत्र को नई दिशा देने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार का लक्ष्य डेयरी क्षेत्र को आत्मनिर्भर, आधुनिक और प्रतिस्पर्धी बनाना है।

जमाखोरों की जेब भर रही है सरकारः दीपक बैज

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में गरीबों को शक्कर न मिलने और उन्हें बाजार से महंगी दरों पर शक्कर खरीदने के लिए मजबूर किए जाने का आरोप लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि साय सरकार गरीबों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। आज प्रदेश की

राशन दुकानों से शक्कर गायब है और गरीब जनता बाजार से महंगे दामों में शक्कर खरीदने को मजबूर है। बस्तर सरगुजा में चना गुड़ महीनों से नहीं मिल रहा है। सुशासन का ढोल पीटने वाली भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ के गरीबों के पेट पर लात मारने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी यह स्पष्ट मांग करती है कि तत्काल सभी पीडीएस दुकानों में शक्कर की आपूर्ति बहाल की जाए, अन्यथा कांग्रेस सड़क से सदन तक उग्र आंदोलन करेगी। भाजपा सरकार अंत्योदय और प्राथमिकता कार्डधारकों को निर्बाध राशन देने का कागजी दावा करती है, लेकिन हकीकत यह है कि प्रदेश की हजारों राशन दुकानों से शक्कर गायब है। सप्लाई चेन का ठप होना और टेंडर प्रक्रिया में देरी सरकार की अक्षमता और प्रशासनिक नाकामी को दर्शाती है। भाजपा सरकार का ध्यान गरीबों के पेट की चिंता करने के बजाय केवल प्रचार-प्रसार पर है।

भाजपा से न सरकार संभल रही और न अर्थव्यवस्थाः शुक्ला

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से राज्य की अर्थव्यवस्था नहीं संभल रही है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन के कारण प्रदेश पर पिछले ढाई सालो में लगभग 1.79 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ गया है। जबकि इन ढाई सालों में सरकार ने कोई बड़ा नया निर्माण कार्य नहीं शुरू किया, कोई

ठोस योजना नहीं बनाया, कोई नई सिंचाई परियोजना, शैक्षणिक औद्योगिक परियोजना नही बनाई। प्रदेश में कोई भी नई सड़के नहीं बनी उसके बाद सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन और गैर उत्पादक खर्चो के कारण राज्य के ऊपर 1.79 लाख करोड़ का कर्जा भाजपा सरकार ने लाद दिया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि 2024 के शुरूआत में सरकार ने 25000 करोड़ का कर्ज लिया। फिर 2024-2025 में 33463 करोड़ का कर्जा लिया। 2025-2026 में 36737 करोड़ का कर्जा लिया। 2026-2027 में अभी तक 40000 करोड़ का कर्जा सरकार ने लिया है। धान खरीदी एवं अन्य योजना आधारित ऋण अलग है। सरकार ने ढाई सालों में 1.79 लाख करोड़ कर्ज लेकर राज्य के हर नागरिक पर कर्जा का बोझ लाद दिया है। सरकार लिये हुये कर्ज के ब्याज अदायगी के रूप में प्रतिवर्ष लगभग 9000 करोड़ रू. खर्च कर रही है।

तीन दिन बंद रह सकते हैं स्कूल-कॉलेज व अन्य संस्थान

रायपुर। छत्तीसगढ़ में 4 सितंबर को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शासकीय अवकाश रहेगा। इस दिन स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। इसके बाद 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और 6 सितंबर को रविवार होने के कारण स्कूल, कॉलेज, बैंक के साथ अन्य संस्थान बंद रहेंगे। बताया जाता है कि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर प्रदेश में 4 सितंबर को शासकीय अवकाश रहेगा। इसके चलते सरकारी कार्यालयों के साथ-साथ स्कूल और कॉलेज भी बंद रहेंगे। जन्माष्टमी को लेकर प्रदेशभर में धार्मिक आयोजन भी होंगे।जन्माष्टमी के अगले दिन यानी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाएगा। यह दिन डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के रूप में मनाया जाता है। हालांकि शिक्षक दिवस पर सभी स्कूलों में अनिवार्य रूप से अवकाश हो, यह जरूरी नहीं है। कई स्कूलों में इस दिन शिक्षक दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। कुछ शिक्षण संस्थानों में स्थानीय व्यवस्था के अनुसार छुट्टी भी हो सकती है। इसके बाद 6 सितंबर को रविवार है। रविवार को स्कूल-कॉलेज समेत अधिकांश सरकारी संस्थानों में साप्ताहिक अवकाश रहता है। इस तरह 4 सितंबर की जन्माष्टमी की छुट्टी, 5 सितंबर की संभावित स्कूल छुट्टी और 6 सितंबर के रविवार को मिलाकर विद्यार्थियों को लगातार तीन दिन छुट्टी मिल सकती है।

एच1एन1 संक्रमण के अब तक 158 मामले आए सामने

रायपुर। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू, एच1एन1 संक्रमण के अब तक 158 मामले सामने आ चुके हैं जिसमें रायपुर में सबसे ज्यादा 66 मरीज मिले हैं, इनमें 58 मरीज ठीक हो चुके हैं जबकि 8 एक्टिव केस हैं। प्रदेश में कुल 121 मरीज रिकवर हो चुके हैं और 37 मरीजों का इलाज चल रहा है। राहत की बात है कि अब तक एच1एन1 से किसी मौत की जानकारी नहीं है।स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में एक दिन में 6 नए एच1एन1 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 158 हो गई है। इनमें से 121 मरीज डिस्चार्ज या होम आइसोलेशन के बाद रिकवर हो चुके हैं। जिलेवार स्थिति देखें तो रायपुर में सबसे ज्यादा 66 पॉजिटिव केस हैं इनमें 58 मरीज रिकवर हो चुके हैं और 8 एक्टिव केस हैं। बिलासपुर में 20, दुर्ग में 17, रायगढ़ में 10 और धमतरी व कोरबा में 9-9 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। राजनांदगांव में 4, बस्तर और बेमेतरा में 3-3 तथा कांकेर, जांजगीर-चांपा, जशपुर, महासमुंद, सक्ती, सूरजपुर सहित कई जिलों में भी एच1एन1 के मामले सामने आए हैं।वर्तमान में एक्टिव केस की बात करें तो दुर्ग में सबसे ज्यादा 9 मरीज उपचाराधीन हैं। रायपुर में 8, कोरबा में 4, रायगढ़ में 3, राजनांदगांव और बस्तर में 2-2 तथा कुछ अन्य जिलों में 1-1 एक्टिव मरीज हैं। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में एच1एन1 से अब तक कोई मौत दर्ज नहीं हुई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण आव्हान का असर

गृह निर्माण मंडल में 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान 'एक पेड़ माँ के नाम' को आगे बढ़ाते हुए प्रकृति संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन और मातृशक्ति के सम्मान के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा इस अभियान की शुरुआत अंबिकापुर से की गई। माननीय मंत्री पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग राजेश अग्रवाल के मुख्य आतिथ्य में सरगवां स्थित अटल विहार योजना में वृक्षारोपण एवं विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण का कार्यक्रम आयोजित किया गया।

मंत्री राजेश अग्रवाल ने इस अवसर पर कहा कि 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान केवल वृक्षारोपण का कार्यक्रम नहीं, बल्कि मातृशक्ति के प्रति सम्मान और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी व्यक्त करने वाला भावनात्मक एवं जनसरोकार से जुड़ा संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू किए गए इस अभियान को जनभागीदारी के माध्यम से व्यापक स्वरूप देना हम सभी की जिम्मेदारी है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी माँ के सम्मान में एक पौधा लगाए और उसे वृक्ष बनने तक संरक्षित करे, यही इस अभियान की वास्तविक सफलता होगी।

उन्होंने कहा कि 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के तहत पूरे प्रदेश में सवा सात करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि कॉलोनी में बाउंड्रीवाल की लगातार मांग की जा रही थी। गृह निर्माण मंडल अध्यक्ष की पहल से आज बाउंड्रीवाल का निर्माण पूर्ण कर उसका लोकार्पण किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष भी 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के अंतर्गत यहां वृक्षारोपण किया गया था और कॉलोनीवासियों के संरक्षण से लगाए गए पौधे अब वृक्ष का रूप ले चुके हैं।अन्य आवासीय योजनाओं एवं कॉलोनियों में भी चलेगा अभियानः गृह निर्माण मंडल अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय वृक्षारोपण अभियान 'एक पेड़ माँ के नाम' को केवल एक कार्यक्रम तक सीमित न रखते हुए छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल की अन्य आवासीय योजनाओं एवं कॉलोनियों में भी चरणबद्ध रूप से संचालित किया जाएगा।उन्होंने कहा कि अंबिकापुर से शुरू हुआ यह अभियान पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ प्रत्येक परिवार और समाज को अपनी माँ के सम्मान में एक पौधा लगाने तथा उसके संरक्षण का संकल्प लेने के लिए प्रेरित करेगा।

बाल संरक्षण को लेकर प्रदेशभर में जागरूकता अभियान तेज

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा, बाल अपराधों की रोकथाम और संकट की स्थिति में त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य बाल संरक्षण समिति के निर्देशन में प्रदेशभर में जागरूकता गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसी कड़ी में रायपुर, बालोद और बेमेतरा की टीमों द्वारा स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा सार्वजनिक स्थलों पर व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों, किशोर-किशोरियों, शिक्षकों, अभिभावकों और आम नागरिकों को बाल संरक्षण से जुड़े कानूनों एवं शासकीय योजनाओं की जानकारी दी गई।

रायपुर जिले में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, भाटागांव द्वारा स्काउट गाइड, बेमेतरा की टीम, बालिकाओं के समूह, धूम्रपान करते पाए गए बालकों तथा आने-जाने वाले यात्रियों को बाल संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान किशोर न्याय अधिनियम 2015 एवं आदर्श नियम 2016, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं नियम 2020, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, दत्तक ग्रहण विनियम 2022 सहित मिशन वात्सल्य, मुख्यमंत्री बाल उदय योजना, बाल सक्षम नीति और बाल संरक्षण नीति की जानकारी दी गई। जागरूकता कार्यक्रम में बाल हिंसा, शोषण, ट्रैफिकिंग, बाल श्रम, बाल तस्करी और साइबर अपराध जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी लोगों को सजग किया गया। साथ ही 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान तथा संकट की स्थिति में उपलब्ध सहायता सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई। किसी भी बच्चे के संकट में होने या बाल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, महिलाओं के लिए 181 तथा आपातकालीन पुलिस सहायता के लिए 112 पर संपर्क करने की जानकारी भी दी गई।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.